PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 224 ● भिलाई, शनिवार 14 मार्च 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

भाजपा की डबल इंजन सरकार

असम के तेज विकास के लिए काम कर रही-पीएम मोदी

गुवाहाटी/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम के दो दिवसीय दौरे के दौरान खराब मौसम की वजह से उनके कार्यक्रम में अचानक बदलाव करना पड़ा। प्रधानमंत्री का आज कोकराझार जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया, जिसके बाद पीएम गुवाहाटी पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया। गुवाहाटी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी गुवाहाटी से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने तीन नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मौसम खराब होने की वजह से मैं कोकराझार नहीं आ पा रहा हूं। मैं आप सभी का क्षमाप्रार्थी हूं। यहां गुवाहाटी से ही आपसे संवाद संभव हुआ है। मैं दिल्ली से निकला था आपके पास आने के लिए, लेकिन मुझे गुवाहाटी में ही उतरना पड़ा और अब मैं यहां से आपके दर्शन भी कर रहा हूं और आपसे बात भी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा-एनडीए की डबल इंजन सरकार असम की विरासत के संरक्षण और असम के तेज विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। आज यहां इस कार्यक्रम में ही इस क्षेत्र के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें से 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बोडोलैंड

की सड़कों के लिए खर्च होने जा रही है। 'असम माला अभियान' के तीसरे चरण से असम की रोड़ कनेक्टिविटी और अधिक सशक्त होगी। इससे पहले, पीएम मोदी ने 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली एक प्रमुख सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना 'असम माला 3.0' की शुरुआत की। इस योजना के तहत, अंतर-राज्यीय संपर्क को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय राजमार्गों व ग्रामीण सड़कों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए असम भर में 900 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) क्षेत्र में लगभग 1,100 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित छह सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें चार फ्लाईओवर और दो पुल शामिल हैं। इन परियोजनाओं से कोकराझार जिले में यातायात जाम कम करने और संपर्क, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण आवागमन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, पीएम मोदी ने कोकराझार जिले के बाशबारी में आवधिक मरम्मत (पीओएच) कार्यशाला की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संपर्क सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई तीन नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई।

कांग्रेस के कार्यकाल में वैश्विक संकट का सीधा असर किसानों पर होता था

पीएम मोदी ने असम में कांग्रेस के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर भी जमकर जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार किसानों के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में भाजपा-एनडीए की सरकार ने आत्मनिर्भरता को लेकर भी अहम फैसले लिए हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में होने वाली लड़ाई का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पहले किसानों पर सीधा असर पड़ता था। कभी खाद महंगी होती थी, कभी डीजल और ऊर्जा पर खर्च बढ़ जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा था। आज सरकार कोशिश इस बात की कर रही है कि डीजल पर खर्च को न्यूनतम किया जा सके।

संक्षिप्त समाचार

मोगा में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग में एक युवक घायल, पुलिस जांच में जुटी

मोगा। पंजाब में मोगा जिले के कस्बा बाघा पुराना क्षेत्र में गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कुलजीत को डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 12 बजे मोगा के तीन नंबर चुंगी के नजदीक कुलजीत सिंह निवासी वेदांत नगर अपने एक साथी के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान एक कार में सवार कुछ अज्ञात युवक वहां पहुंचे और उन्होंने अचानक कुलजीत सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान कुलजीत सिंह के पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल युवक को उठाकर उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कुलजीत सिंह की हालत गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद लुधियाना के डीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।

अमित शाह के दौरे पर बोले तरुण चुघ, पंजाब बदलाव के लिए तैयार है

चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि यह गर्व की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब आ रहे हैं। तरुण चुघ ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब असली बदलाव की ओर बढ़ रहा है। पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस बदलाव को लीड करने और इसे लाने में अहम भूमिका अदा कर रही है। पंजाब बदलाव के लिए तैयार है।

आगामी चुनाव से पहले सीएम बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक

एससी-एसटी ओबीसी समुदायों को लुभाने के लिए किया एलान

कोलकाता/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने एक नया राजनीतिक और सामाजिक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार मुंडा, कोरा, डोम, कुंभकार और सदगोप समुदायों के लिए नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाएगी। सीएम ममता के अनुसार यह कदम न केवल इन कमजोर और पिछड़े समुदायों के अधिकारों और परंपराओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में तरक्की को भी बढ़ावा देगा। सीएम

बनर्जी ने इसे राज्य में समान और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताया है, जो चुनावी मोर्चे पर भी उनकी पकड़ मजबूत कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में सीएम ममता ने लिखा कि मैं खुशी के साथ घोषणा करती हूं कि हमारी सरकार मुंडा (एसटी), कोरा (एसटी), डोम (एससी), कुंभकार (ओबीसी) और सदगोप (ओबीसी) समुदायों के लिए जल्द ही पांच नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाएगी। अपने पोस्ट में सीएम ममता बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये पांचों समुदाय राज्य की सजीव और रंगीन संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। बोर्डों के जरिए इनके भाषा, परंपरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े अधिकारों की रक्षा की जाएगी। सीएम बनर्जी ने यह भी बताया कि 2013 से उनकी सरकार ने कई ऐसे बोर्ड स्थापित किए हैं, जिससे कमजोर समुदायों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया गया है।

व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाना उचित नहीं, होर्मुज हमले पर भारत ने उठाई आवाज

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 11 मार्च को होर्मुज जलडमरूमध्य में थाई जहाज मयूरी नारे पर हुए हमले की खबरों पर गहरी चिंता जताई है। मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में थाई जहाज मयूरी नारे पर हुए हमले की खबरों की जानकारी मिली है। यह जहाज भारत के कांडला बंदरगाह के लिए जा रहा था। मंत्रालय ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान व्यावसायिक जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया जा रहा है।

स्वाति मालीवाल ने खोली पोल

अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच गठजोड़ बन गया है....

नयी दिल्ली/ एजेंसी

निजी अस्पतालों में महंगे इलाज और निजी एवं चिकित्सा बीमा कंपनियों द्वारा मरीजों के दावे मनमाने तरीके से खारिज किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने मांग की कि इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए स्वाति ने कहा कि आज निजी अस्पतालों और निजी बीमा कंपनियों के बीच गठजोड़ बन गया है जो आम इंसान की कमर तोड़ रहा है। उन्होंने कहा मरीज की अस्पताल में मौत हो

जाती है। निजी बीमा कंपनी क्लेम देने से मना कर देती है। पूरा भुगतान न होने पर अस्पताल शव देने से मना कर देता है। गरीब परिवारों के लिए ऐसे में कर्ज लेने या अपना घर, गहने बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। स्वाति ने कहा कि निजी बीमा कंपनी जानीमानी हस्तियों से प्रचार करवाती हैं और विज्ञापनों में कहा जाता है कि मिनटों में क्लेम मिलेगा। इस झांसे के बाद व्यक्ति निजी अस्पताल और निजी बीमा कंपनी के बीच टेनिस बॉल बन जाता है। अस्पताल में भर्ती होते ही टीपीए में पता चलता है कि आपकी बीमा कंपनी काली सूची में है। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं है तो दावा बार-बार खारिज होता रहता है। कभी कहा जाता है कि पहले भुगतान करो फिर क्लेम मिलेगा। अगर क्लेम फाइल हो भी गया तो डिस्चार्ज वाले दिन भी एक कागज के लिए पूरा दिन बैठे रहना पड़ता है।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा

सपा-कांग्रेस में इस्तेमाल करने की चतुरता नहीं....

लखनऊ। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि सपा, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल इतना चतुर नहीं है कि मुझे चुनाव में इस्तेमाल कर सके। हम किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि गंगा और गोरक्षा जैसे मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं, जो पहले से भाजपा के भी प्रमुख विषय रहे हैं। चाहे तो भाजपा भी मेरे समर्थन में आ सकती है। चुनाव में किसी की चालाकी से मेरा इस्तेमाल हो जाना संभव नहीं है। ये बातें उन्होंने बृहस्पतिवार को अमर उजाला से खास बातचीत में कहीं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लखनऊ के हासेमऊ स्थित गोशाला में बृहस्पतिवार

को गो पूजन कर गोरक्षा के लिए धर्मयुद्ध का ऐलान किया। इसी के साथ उन्होंने गो प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान की शुरुआत करते हुए चतुरंगिणी सेना बनाने की घोषणा की। शंकराचार्य ने ऋग्वेद के पद अहम् हनन् वृत्ते गविष्ठे का अनुयायियों से सामूहिक जाप कराया।

दांडी मार्च की वर्षगांठ पर जयपुर में कांग्रेस का साइलेंट मार्च, अशोक गहलोत बोले देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात

जयपुर। नमक सत्याग्रह और ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जयपुर में भारत सेवा संस्थान द्वारा एक साइलेंट मार्च (मौन जुलूस) का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1930 की दांडी यात्रा के ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र करते हुए वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कड़ा प्रहार किया।

इच्छामृत्यु की इजाजत

मेरी नहीं, उन मां-बाप की जीत,जिन्होंन बिना फीस हाईकोर्ट से सुप्रीमकोर्ट तक लड़ी हरीश की लड़ाई

गाजियाबाद। अधिवक्ता मनीष जैन ने बिना किसी फीस के हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हरीश राणा का केस लड़ा। वह कहते हैं कि यह मेरी जीत नहीं, बल्कि उन माता-पिता की जीत है, जो अपने जिगर के टुकड़े के लिए 13 वर्षों तक संघर्ष करते रहे। मनीष बताते हैं कि जब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने आठ नवंबर 2024 को इस मामले में संवेदनशील आदेश दिए। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को हरीश के लिए चिकित्सा सहायता और समुचित देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इससे केस को एक नई मानवीय दिशा मिली थी। मनीष ने बताया कि मोहन नगर में ब्रह्माकुमारी लवली दीदी के माध्यम से उनकी मुलाकात अशोक राणा से

हुई। दीदी ने अनुरोध किया कि अदालत के जरिये मदद करें। पहले दिल्ली हाईकोर्ट, फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। मनीष कहते हैं कि यह केस सिर्फ कानूनी बहस नहीं था, बल्कि एक पिता और मां की टूटी उम्मीदों की कहानी था। वेंटिलेटर पर अपने बेटे को हर दिन देखना किसी भी इंसान के लिए असहनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के साथ करुणा को भी महत्व दिया। मनीष कहते हैं कि अगर इस फैसले से एक पिता को मानसिक शांति और एक बेटे को पीड़ा से मुक्ति मिली तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार धनंजय कहते हैं कि यह फैसला वर्ष 2018 के कॉमन कॉज सिद्धांत पर आधारित है। भारत में यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें कोर्ट ने सीधे तौर पर इच्छामृत्यु की मंजूरी दी। अदालत ने एम्स को निर्देश दिए कि हरीश के जीवन रक्षक उपकरण गरिमा के साथ हटाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा न हो। यह निर्णय भविष्य में उन परिवारों के लिए रास्ता खोलेगा, जो असाध्य बीमारी और निरंतर पीड़ा से जूझ रहे हैं। कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि जीवन की गरिमा, केवल जीवन को खींचते रहने में नहीं, बल्कि सम्मानजनक विदाई में भी होती है।

हेगसेथ का बड़ा बयान

लगभग खत्म हो चुकी ईरान की सैन्य ताकत अब तक 15000 लक्ष्यों को बनाया निशाना

बीजिंग। एजेंसी

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ईरान की कट्टरपंथी सेना को इस तरह तबाह कर रहा है, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने बताया कि अमेरिका और इस्राइल की वायु सेनाओं ने मिलकर दुश्मन के अब तक 15 हजार से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया है, यानी प्रतिदिन एक हजार से अधिक लक्ष्य। अभी भी हमारे लड़ाकू विमान और बमवर्षक पूरे दिन ईरान के ऊपर उड़ान भर रहे हैं और खुफिया जानकारी के अनुसार लक्ष्य तय कर रहे हैं। हेगसेथ ने कहा कि दुष्ट शासन का सबसे बड़ा दुःस्वप्न। ईरान के पास कोई वायु रक्षा नहीं है। ईरान के पास कोई वायु सेना नहीं है। ईरान के पास कोई नौसेना नहीं है। उनके मिसाइल, मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन या तो नष्ट किए जा रहे हैं या हवा में मार दिए जा रहे हैं। उनके मिसाइल भंडार में 90 फीसदी की कमी आ चुकी है। उनके एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन कल 95 फीसदी तक कम हो गए थे और जैसा कि दुनिया देख रही है, वे हॉर्मुज की खाड़ी में घबराहट और हताशा में हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम देख रहे हैं, इससे निपट रहे हैं और इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने

कहा, हम उनकी सैन्य क्षमताओं को इस तरह हराने, नष्ट करने और निष्क्रिय करने की योजना पर काम कर रहे हैं, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ईरान के पास अब कोई सक्रिय वायु सेना नहीं है। उनकी पूरी नौसेना फारस की खाड़ी में नष्ट हो चुकी है और उनके मिसाइल बल दिन-प्रतिदिन घट रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि उनके पास अब और उत्पादन करने की क्षमता भी नहीं है। बहुत जल्द ईरान की सभी रक्षा कंपनियां नष्ट हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, दो दिन पहले तक ईरान की पूरी बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन क्षमता और उन मिसाइलों के प्रत्येक घटक का निर्माण करने वाली कंपनियां पूरी तरह नष्ट कर दी गई हैं। ईरान भर में भवन, संयंत्र और फैक्टरी लाइनों को नष्ट कर दिया गया है। हम उनके पास मौजूद मिसाइलों को मार रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास और (मिसाइल) बनाने की क्षमता न रहे।

वैश्विक चुनौतियों से निपटने की तैयारी

सरकार ने बनाया आर्थिक स्थिरीकरण फंड-निर्मला..

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण कोष (इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड) सरकार को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय मदद देगा। लोकसभा में पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह फंड पश्चिम एशिया जैसी जगहों पर अचानक पैदा होने वाली समस्याओं से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले झटकों को संभालने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण फंड भारत को वैश्विक

परिस्थितियों से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्तीय गुंजाइश देगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 2.81 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति लोकसभा से मांगी है। लेकिन सरकार को 80 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आय भी मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण 45 दिन और शहरी क्षेत्र के घरेलू गैस उपभोक्ता 25 दिन बाद कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग, कमर्शियल की बुकिंग 45 दिन में

डौंडी क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामार कार्यवाही कर 6 घरेलू सिलेंडर किए गए जब्त

बालोद। जिले में घरेलु एलपीजी गैस का स्टॉक सभी वितरक एजेंसियों के पास पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। अपर कलेक्टर अजय किशोर लकरा ने गुरुवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष मे जिले के 11 एलपीजी एजेंसी संचालकों की बैठक लेकर उपभोक्ताओं को सुव्यवस्थित रूप से एलपीजी गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु चर्चा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में घरेलु गैस सिलेण्डर की निर्बाध आपूर्ति, बुकिंग नियमों और अवैध व्यावसायिक उपयोग पर कड़ाई के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान एजेंसी संचालकों ने बताया कि सॉफ्टवेयर के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता एक निश्चित अवधि के बाद ही अगली रिफिल बुक कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता रिफिल प्राप्ति के 45 दिन बाद एवं शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता रिफिल प्राप्ति के 25 दिन बाद बुकिंग कर सकते हैं। निर्धारित अवधि से पूर्व की गई बुकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे इस निर्धारित समयावधि के पश्चात ही ऑनलाइन बुकिंग करें। बैठक में बताया गया कि जिले में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। बालोद क्षेत्र के लिए बुकिंग के 5 से 6 दिन एवं अन्य क्षेत्र हेतु अधिकतम 5 दिनों के भीतर रिफिल की आपूर्ति किए जाने की जानकारी दी। सभी संचालकों को स्टॉक की उपलब्धता और रिफिल दर अपने परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने तथा ऑयल कंपनियों को समय पर राशि प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की टीम द्वारा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को डौंडी क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामार कार्यवाही कर 6 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जिला प्रशासन ने होटल, ठेला और गुमटी संचालक घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न करने की अपील की है।

भंडारण की स्तिथि में की जा रही एडवांस बुकिंग

अपर कलेक्टर अजय किशोर लकरा ने बताया कि जिले के सभी 11 गैस एजेंसियों की बैठक ली गई है। बैठक को सभी को गैस का भंडारण पर्याप्त रखने निर्देशित किया है। जिले में गैस सामान्य तरीके से वितरित हो रहा है। लेकिन फिर भी भविष्य के सचेत करते हुए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखे हुए है। आने वाले भंडारण की स्तिथि में एडवांस बुकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि एजेंसी के बाहर भी लिस्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होने बताया कि कमर्शियल गैस भी 45 दिन में बुकिंग कराना है।

बिना बुकिंग के हितग्राहियों को गैस सिलेंडर नही देने के निर्देश

जिला खाद्य अधिकारी तुलसी ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता 45 दिन और शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता 25 दिन बाद ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। निर्धारित दिन से पहले बुकिंग करने से सॉफ्टवेयर में बुकिंग नही हो रही है। प्रत्येक गैस वितरक को निर्देशित किया गया है कि ऑफिस और गोडाउन में स्टॉक को दर के साथ मे उपलब्ध स्टॉक को प्रदर्शित कर के रखें। सेल्समैन को बिना बुकिंग के हितग्राहियों को गैस सिलेंडर नही देने के संबंध मे निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि अतिआवश्यक सेवा के अंतर्गत बालोद और डौंडी के लिए 10-10 सिलेंडर और अन्य गैस वितरकों को 5-5 गैस सिलेंडर का रिजर्व स्टॉक रखने निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि बालोद मे बुकिंग के 5-6 दिन बाद और अन्य स्थानों मे 3-4 दिन मे बुकिंग के बाद सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है।

पीएम अभ्युदय अजय योजना में आवेदन पत्र 16 मार्च तक

धमतरी। छग राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम रायपुर द्वारा जिला धमतरी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रधानमंत्री अजय अभ्युदय योजना में 218 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। उक्त योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से रू 1,00,000 एक लाख न्यूनतम तक ऋण तथा अनुदान राशि रू 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुदान से 50,000 विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने के लिए दिए जाने का प्रावधान है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार आवेदन पत्र पशु चिकित्सा विभाग, बिहान, जनपद पंचायत एवं कार्यालय द्वारा शिविर आयोजित कर प्रचार.प्रसार के माध्यम से कुल 278 आवेदन पत्र तैयार किये गये थे, जिन्हे स्वीकृति की कार्यवाही हेतु संबंधित बैंकों को प्रेषित किये गये है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित धमतरी ने बताया कि बैंको को प्रेषित आवेदन पत्रों मे युनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफबड़ौदा एवं छग राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा कुल 26 ऋण प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान कर अनुदान राशि की मांग की गई है। बैंको को प्रेषित की गई ऋण प्रकरणों में उपयुक्त प्रकरण नहीं होने का उल्लेख करते हुये 27 ऋण प्रकरण बैंको द्वारा वापस किये गये है। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यालय द्वारा प्रेषित ऋण प्रकरणों में कुल 225 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु बैंक में लंबित है। वित्तीय वर्ष 2025.26 समाप्ति की ओर है आवेदको से आवेदन पत्र 16 मार्च 2026 तक कार्यालय में जमा लिये जायेंगे।

काउंसिलिंग सह पंजीयन आज

धमतरी। जल जीवन मिशन के तहत जिले के प्रत्येक पंचायतों में नलजल मित्र कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हित पात्र युवाओं को बहु.कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करने लाईवलीहुड कॉलेज में जल वितरण संचालक में प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके तहत आगामी 13 मार्च को सुबह 10 बजे लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में काउंसिलिंग सह पंजीयन किया जाएगा। कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज अबिनाश मिश्रा ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जनपद क्षेत्र से ऐसे चिन्हित पात्र युवाओं, जिनका नलजल कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण नहीं हुआ है, उन युवाओं को 13 मार्च 2026 को लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

बिना सत्ता संरक्षण के इतनी बड़ी मात्रा में अफ़ीम खेती संभव नहीं : तारिणी

धमतरी। कांग्रेस ने दुर्ग जिले के समोदा और बलरामपुर जिले में अफीम की खेती के मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में नशे का कारोबार चल रहा है। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर भाजपा कार्यालय का रास्ता बंद कर दिया था, जिसे कांग्रेसियों ने पार करने की कोशिश की। कांग्रेस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दुर्ग जिले के समोदा गांव व बलरामपुर जिले से अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदेश सरकार को घेर रही है और अफीम की खेती के साथ नशे के कारोबार को भाजपा सरकार द्वारा संरक्षण देने

व भाजपाईयों के संलिप्तता के आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी द्वारा जिला भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। कांग्रेसियों द्वारा घेराव करने रैली के शक्ल में पदयात्रा करते हुए निकले और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि पुलिस द्वारा पहले ही बेरिकेट्स लगाकर भाजपा कार्यालय का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था जिस पर कांग्रेसियों ने चढ़कर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष तारिणी चन्द्राकर ने कहा कि बिना सत्ता के संरक्षण के इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति के फार्म हाउस में अफीम की खेती की बात सामने आई है वह भाजपा का सक्रिय पदाधिकारी है और पार्टी के कई कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रही है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ भी मौजूद है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। लेकिन सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। लेकिन सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। गांजा, अफीम और अन्य नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार लगातार बढ़ रहा है जिसका सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ रहा है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खुले आम नशीले पदार्थ का कारोबार हो रहा है तो इसके पीछे कौन लोग हैं इसका खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा कार्यालय घेराव के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष तारिणी चन्द्राकर, पूर्व जिलाध्यक्ष शरद लोहाना, मोहन लालवानी, पूर्व महापौर विजय देवांगन, पूर्व दुग्ध महासंघ अध्यक्ष विपिन साहू, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशु चन्द्राकर, अरविंद दोशी, शहर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष गौतम वाधवानी, योगेश शर्मा, आलोक जाधव, पूर्व शहर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष आकाश गोलछा, कविता बाबर, मनीषा साहू, वातांजलि गोस्वामी, प्रकाश पवार, नरेश जसूजा, राजेश पाण्डेय, यश राजपुत, शास्त्री सोनवानी, कृष्णा मरकाम, रोशनी पवार, आशुतोष खरे, सूरज पासवान, अजय डहरिया, संजू साहू, योगेश लाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे।

रायपुर के अजीत कोटक द्वारा सार्थक के विशेष बच्चों के लिए परीक्षा पूर्व फ्रूट, जूस पार्टी का आयोजन

धमतरी। धमतरी स्थित मानसिक दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र सार्थक स्कूल में परीक्षाओं के प्रारंभ होने से पूर्व रायपुर निवासी अजीत कोटक ने विशेष बच्चों के लिए फ्रूट एवं जूस पार्टी का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को विभिन्न प्रकार के ताजे फल और जूस प्रदान किए। बच्चों ने बड़े आनंद और उत्साह के साथ फल और जूस लिया जिससे उनके चेहरों पर खुशी और संतोष स्पष्ट झलक रहा था। ज्ञात हो किए रायपुर निवासी अजीत कोटक, जो सार्थक की सचिव स्नेहा राठौड़ के

जीजाजी हैं, राठौड़ ने बताया कि उनके जीजाजी को सार्थक के बच्चों से विशेष लगाव है। वे समय.समय पर धमतरी आकर बच्चों से मिलते हैं और उनके लिए स्वल्पाहार, फल, जूस अथवा गर्मी के दिनों में ठंडा शर्बत आदि की व्यवस्था करते हैं। बच्चों के साथ समय बिताकर और उनके चेहरों पर खिली मुस्कान देखकर उन्हें भी अत्यंत संतोष और प्रसन्नता होती है। इस अवसर पर सार्थक अध्यक्ष डॉ सरिता दोशी ने जानकारी दी कि विशेष बच्चों को भी परीक्षा का काफी तनाव होता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसे कम करने के लिए बच्चों को पढ़ाई का नियमित रिवीजन कराया जाता है तथा परीक्षा से पूर्व उनके लिए फ्रूट एवं जूस की व्यवस्था किसी न किसी सहृदय व्यक्ति द्वारा की जाती है। फ्रूट पार्टी जैसे आयोजनों से बच्चों को ताजगी और ऊर्जा मिलती है और वे काफी प्रफुल्लित रहते हैं। अजीत कोटक ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दीं और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सार्थक की प्रशिक्षक मैथिली गोड़े, देविका दीवान, काजल रजक, कौशिल्या यादव तथा सुनैना गोड़े उपस्थित थीं।

भक्त माता कर्मा जयंती पर काण्डेकेला में अष्टपहरी संकीर्तन नामयज्ञ 14 से

काण्डेकेला। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम काण्डेकेला में भक्त माता कर्मा जयंती एवं सामुदायिक भवन उद्घाटन के पावन अवसर पर श्री श्री अष्टपहरी संकीर्तन नामयज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह धार्मिक कार्यक्रम 14 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होकर धर्मलाभ प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 14 मार्च शनिवार को दोपहर 4:00 बजे कलश यात्रा के साथ होगी। इसके पश्चात संध्या समय देवपूजन एवं अधिवास की विधि संपन्न की जाएगी। 15 मार्च रविवार को प्रातः 8:30 बजे से ब्रह्म नाम जाप का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें संकीर्तन मंडलियां भगवान श्री राम

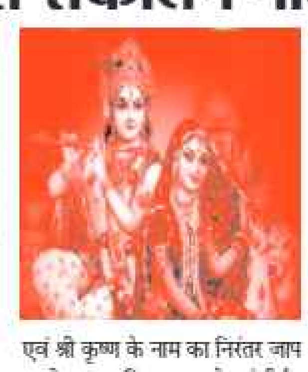

एवं श्री कृष्ण के नाम का निरंतर जाप करते हुए भक्ति-भाव से संकीर्तन प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम का समापन 16 मार्च सोमवार को दोपहर 12:30 बजे ब्रह्म नाम समापन के साथ होगा। इसके बाद नगर भ्रमण, दही हांडी फोड़ एवं पूर्णाहुति का आयोजन किया जाएगा। इस पावन अवसर पर ग्राम काण्डेकेला, भाठीपारा, बुरजाबहाल, देवभोग, निष्ठीगुड़ा एवं भालूकटा (ओडिशा) की संकीर्तन मंडलियों को आमंत्रित किया गया है। ये मंडलियां भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हुए अपनी भक्ति, नृत्य और कला का प्रदर्शन करेंगी। आयोजकों ने बताया कि अष्टपहरी नामयज्ञ का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, सुख-समृद्धि और आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया जाएगा तथा क्षेत्र की खुशहाली और लोगों के कल्याण की कामना की जाएगी। कार्यक्रम के आयोजन में आयोजक समिति के साथ कर्ता-मुलचंद साहू, डालिमो साहू, तथा धार्मिक अनुष्ठान के संचालन हेतु आचार्य पं. हरलाल मिश्रा और पं. मदनप्रसाद मिश्रा की विशेष भूमिका रहेगी।

आबकारी विभाग की कार्रवाई, 81हजार रुपए के महुआ शराब एवं लाहन जब्त

बलौदाबाजार। आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने गुरूवार को कार्रवाई करते हुए 81 हजार रुपये के अवैध महुआ शराब एवं महुआ लाहन जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कसडोल वृत्त के अंतर्गत आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी श्याम पटेल हाल मुकाम ग्राम सैहाभाटा थाना कसडोल के कब्जे से 45 बल्क लीटर महुआ शराब, बाजार मूल्य 9 हजार रूपये होना पाया गया एवं 30 किलोग्राम क्षमता वाली प्लास्टिक बोरी में 40 नग कुल 1200 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। महुआ लाहन का बाजार मूल्य 72 हजार रूपये होना पाया गया। महुआ लाहन की सेम्पल लेकर सभी लाहन को मौके पर नष्ट किया गया। आरोपी श्याम पटेल के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क) (च), 34(2), 59(क) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उक्त कार्रवाई में सहायक आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम, पी.माधव राव, विनोद कुमार बांधे, नगर सैनिक कमल वर्मा, दुर्गेश्वरी कुर्रे एवं राजकुमारी पैकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कलेक्टर ने पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं,अधिकारियों को दिये त्वरित निराकरण के निर्देश

बलौदाबाजार। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने विकासखण्ड भाटापारा भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत तरेंगा में पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनी। उन्होंने ग्रामीणों की मांगो और शिकायत का त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। ग्रामीणों ने मिडिल स्कूल में शिक्षकों के विलम्ब से पहुंचने और बच्चों पर नियंत्रण की कमी तथा शाला विकास समिति की बैठक व फण्ड की पारदर्शिता की समस्या बताई। इस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन पर निर्देशित किया कि कल ही बीईओ और बीआरसी को स्कूल भेजकर स्कूल की व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिये। इसीतरह प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, पहुंच मार्ग की समस्या का भी जल्द निराकरण के निर्देश दिये। इसके पश्चात् कलेक्टर ने टीटीसी लाइब्रेरी परिसर में पीपल पौधे का रोपण किया वहीं लाइब्रेरी भवन के पास मोर गांव, मोर पानी अभियान के तहत सोखता गड्ढा निर्माण में श्रमदान कर लोगों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान उप सरपंच की मांग पर लाइब्रेरी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु जनपद सीईओ को प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्राम के नवनियुक्त पुलिस आरक्षको को शुभकामनायें दी और वहां बनाये गए जिम सेंटर की भी सराहना किये। इस दौरान सी ई ओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, एसडीएम श्यामा पटेल सहीत अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

डॉ, वर्षा मिश्रा को मिला नारी शक्ति गौरव सम्मान 2026

बलौदाबाजार। बुजुर्गों की चौपाल संस्था के 115 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था द्वारा 115 उत्कृष्ट महिलाओं का सम्मान नारी शक्ति गौरव सम्मान के रूप में महिलाओं का सम्मान किया 8 मार्च 2026 रविवार सुबह 11:00 बजे विमतरा सभागृह मधु पिल्ले चौक शांति नगर रायपुर में आयोजित किया इसमें बलौदाबाजार जिले से कसडोल की डॉ, वर्षा मिश्रा (शर्मा)को नारी शक्ति गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया इन्हे यह सम्मान समाज सेवा के लिए दिया गया इसी ऐतिहासिक पड़ाव को स्मरणीय बनाने हेतु नारी चौपाल द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 115 प्रेरणादाई एवं उत्कृष्ट महिलाओं को

सम्मानित किया गया कार्यक्रम के संस्थापक प्रशांत पांडेय अध्यक्ष डॉ, आरती उपाध्याय कार्यक्रम प्रभारी पदमा शर्मा जी थी उक्त कार्यक्रम में वर्णिका शर्मा बाल आयोग अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मोना सेन रायपुर महापौर मीनल चौबे नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे सजय श्रीवास्तव जी ने कहा महिला शक्ति समाज की आधारशिला है और सम्मान सशक्तिकरण आर्थिक मजबूती से ही समाज आगे बढ़ेगा और देश विकसित बनेगा उन्होंने कहा कि महिला केवल परिवार तक सीमित नही बल्कि समाज व राष्ट्र के विकास में भी निर्णायक भूमिका निभाती है रायपुर महापौर मीनल चौबे ने भी नारी की प्रशंसा करते हुए नारी को शक्ति का रूप बताया और आज हर क्षेत्र मे उनको आगे बढ़ता बताया उत्त कार्यक्रम में प्रशांत पांडेय डॉ आरती उपाध्यक्ष कार्यक्रम प्रभारी पदमा शर्माअमरजीत सिंह छाबड़ा कर्णिका जैन लोकेश कांवरिया ममता साहू प्रतिष्ठा हरितवाल शामिल हुए।

भारत स्काउट गाइड के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से की सौजन्य भेंट

बलौदाबाजार। कलेक्टर कुलदीप शर्मा से भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर जिले में स्काउटिंग की प्रगति के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।कलेक्टर शर्मा ने जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में स्काउट गाइड की संचालन, गतिविधियों सहित कार्य मो की जानकारी ली और विस्तार के सम्बन्ध में भी चर्चा की। इस अवसर पर जिला मुख्य आयुक्त डॉ अजय राव, जिला अध्यक्ष रामधार पटेल, लीडर ट्रेनर के आर कश्यप, जिला कोषाध्यक्ष पीयूष मिश्रा, जिला आयुक्त गाइड वंदना तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

जिले में घरेलू एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता,आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी के निर्देश

कलेक्टर ने एलपीज़ी वितरकों के साथ की बैठक

बलौदाबाजार। जिले में घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था हेतु बुधवार को संयुक्त जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले के घरेलु एलपीज़ी गैस वितरकों के साथ बैठक कर जिले में रसोई गैस की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि सभी एजेंसियो में उपभोक्ताओं सामन्य रूप से व प्रचलित मूल्य पर एलपीज़ी गैस उपलब्ध कराएं। कहीं पर भी एजेंसी के द्वारा शॉर्टेज की स्थिति निर्मित न हो। कालाबाजारी या अधिक मूल्य पर बेचने की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी वितरक एलपीज़ी भण्डारण एवं वितरण की पंजी संधारित करें और विभागीय अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं। उन्होंने कामर्शियल एलपीजी के लिये उचित समन्वय स्थापित कर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि जिले में इंडियन ऑयल एवं हिंदुस्तान ऑयल कम्पनी के कुल 22 वितरक हैं। उपस्थित वितरकों ने अवगत कराया कि जिले में घरेलु एलपीज़ी की पर्याप्त उपलब्धता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है।कमर्शियल के लिये भी समन्वय बनाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियो ने बताया कि एलपीज़ी आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

सरकारी स्कूलों में शौचालयों की कमी उत्पीड़न का रूप -हाईकोर्ट

रायपुर। छग प्रदेश के 25 वर्ष होने के बाद भी सरकारी स्कूलों विशेषकर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय की समस्या लंबे समय से विद्यमान है। शौचालय की सुविधा नहीं होने से छात्राओं की स्थिति काफी गंभीर है। यह महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है जिस पर अब तक सरकार ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाए है। उक्त विषय पर छग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान लगी जनहित याचिका पर सख्त रूख अपनाते हुए छग शासन के शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में डबल बेंच ने हिंदी दैनिक में मुद्रित एक समाचार पर भी संज्ञान लिया है और उस पर शिक्षा सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ज्ञातव्य है कि रिपोर्ट के अनुसार छग में 5 हजार से अधिक स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। जबकि आठ हजार स्कूलों में शौचालयों की स्थिति बेहद खराब है। 160 से अधिक स्कूलों में शौचालय ही नहीं है ऐसी स्थिति में बालिकाओं के लिए शौच आदि से निवृत होना कठिन समस्या है। हाईकोर्ट को जनहित याचिका के माध्यम से यह भी जानकारी मिली है कि 200 से अधिक स्कूलें में शौचालय उपयोग योग्य नहीं है। राज्य भर में 56,615स्कूलों में से 54715 स्कूलों में शौचालय है। जिनमें से 52 545 ही उपयोग योग्य है।

पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद बना आजीविका का साधन

रायपुर। पारंपरिक कौशल, जैसे मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई और लकड़ी का काम, स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के माध्यम से न केवल रोजगार प्रदान करता है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – बिहान योजना के तहत जशपुर जिले की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल गढ़ रही हैं। कांसाबेल विकासखंड के ग्राम सेम्हर कछार की हरियाली स्व-सहायता समूह की 11 महिलाओं ने छिंद कासा से आकर्षक टोकरी और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका को मजबूत किया है। समूह की सदस्य श्रीमती बालमुनि भगत ने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिला। पहले महिलाएं केवल घरेलू कामकाज तक सीमित थीं, लेकिन अब वे अच्छी कमाई कर रही हैं। यह कार्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ आत्मविश्वास भी दे रहा है। उन्होंने बताया कि यह न केवल एक व्यवसाय है, बल्कि यह परंपराओं, कौशल और सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है। महिलाओं ने बताया कि बिहान योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। समूह के माध्यम से प्रशिक्षण, सहयोग और विपणन सुविधा मिलने से उनका उत्पाद अब स्थानीय हाट-बाजार और मेलों में लोकप्रिय हो चुका है। महिलाएं कहती हैं कि अब वे सिर्फघर तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अपनी पहचान खुद बना रही हैं।

स्कूलों के आसपास नशे का कारोबार! नगर निगम की रेड में गुटखा-सिगरेट के पाउच जब्त, पान दुकानदारों को सख्त चेतावनी

रायपुर। राजधानी में स्कूलों के आसपास खुलेआम बिक रही नशे की सामग्री पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक-4 में नगर निवेश विभाग के उड़नदस्ता दल ने छत्तीसगढ़ कॉलेज, संत कँवरराम स्कूल और हिंदू हाई स्कूल समेत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास संचालित पान दुकानों पर औचक निरीक्षण कर बड़ी मात्रा में गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला के पाउच जब्त किए। यह कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश तथा नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर की गई। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि कई पान दुकानों में छात्रों के आसपास नशे से संबंधित सामग्री बिक्री के लिए रखी गई थी। मौके पर ही नगर निगम की टीम ने कोटपा एक्ट के प्रावधानों के तहत इन सभी नशीले उत्पादों को जब्त कर लिया। नगर निगम जोन-4 की जोन कमिश्नर डॉ. दिव्या चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में कार्यपालन अभियंता शेखर सिंह, सहायक अभियंता दीपक देवांगन, गुलाबचंद कर्ष सहित नगर निवेश विभाग और निगम मुख्यालय के उड़नदस्ता दल के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने संबंधित पान दुकान संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोबारा स्कूलों के आसपास गुटखा, तंबाकू, सिगरेट या अन्य नशीली वस्तुओं की बिक्री करते पाए गए तो कोटपा एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की इस अचानक कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही। अधिकारियों ने साफकर दिया है कि बच्चों और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे कारोबारियों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा।

गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा

रायपुर। रायपुर कोर्ट ने गांजा तस्कर मनीष और निखिल को 15-15 साल की सजा सुनाई है साथ ही डेढ़- डेढ़ लाख रूपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। उक्त सजा कोर्ट ने कुल 14 गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाया है। बता दें कि गांजा तस्करी के मामले में मनीष सिंह और निखिल यादव के खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। दोनों आरोपी ट्रायल से बचने के लिए उड़ीसा में मेन सप्लायर के ठिकानों पर जाकर छिपे थे, जिन्हें क्राईम ब्रांच की टीम ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सजा सुनाई है दोनों आरोपियों को 15-15 साल की सजा सुनाई है साथ ही डेढ़- डेढ़ लाख रूपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। कोर्ट ने कुल 14 गवाहों की गवाही के आधार पर सजा सुनाई है। यह भी बता दें कि तस्करों के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर के दिशा-निर्देश में नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से उनकी खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

बिहान परियोजना से मिला आत्मनिर्भरता का संबल

सिलाई सेंटर और मिनी राइस मिल से प्रतिमाह 20 से 30 हजार की आय

- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने लखपति संवाद कार्यक्रम में किया सम्मानित

रायपुर/ संवाददाता

मुंगेली जिले के पथरिया विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम गोइन्द्री की निवासी श्रीमती शांतामणी गेंदले आज ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और संघर्ष से सफलता की मिसाल बन गई हैं। कभी आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ से जूझने वाली शांतामणी ने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास तथा स्व-सहायता समूह के सहयोग से न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को बिहान परियोजना के नाम से संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसी परियोजना से जुड़कर शांतामणी गेंदले ने भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की नई शुरुआत की। शांतामणी गेंदले संस्कार महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और ग्राम संगठन तथा संकुल स्तरीय संगठन (सीएलएफ) में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में वे एफएलसीआरपी (वित्तीय साक्षरता सामुदायिक संसाधन व्यक्ति) के रूप में भी कार्य करते हुए ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित लखपति संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कुछ वर्ष पूर्व तक शांतामणी का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था।

सीमित आय और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे परिवार का भरण-पोषण करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तब आया जब वे बिहान परियोजना के अंतर्गत संचालित संस्कार महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने नियमित बचत की आदत विकसित की और वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों को समझा। समूह के माध्यम से उन्हें रिवॉल्विंग फंड (आरएफ) और सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) की सहायता प्राप्त हुई। इसके साथ ही बैंक लिंकेज तथा संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से उन्हें ऋण सुविधा भी मिली, जिससे उन्होंने आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। प्राप्त ऋण राशि का उपयोग उन्होंने आय बढ़ाने वाले कार्यों में निवेश के रूप में किया। उन्होंने अपने गांव में सिलाई सेंटर प्रारंभ किया, जहां वे सिलाई का कार्य करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने मिनी राइस मिल की स्थापना कर गांव में ही धान कुटाई की सुविधा उपलब्ध कराई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आज वे प्रतिमाह लगभग 20 हजार से 30 हजार रुपये की आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है। शांतामणी की उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं हैं। एफएलसीआरपी के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने 60 से अधिक स्व-सहायता समूहों को लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपये की ऋण राशि उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 30 समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिलाने में सहयोग किया तथा 80 से अधिक समूहों को वित्तीय साक्षरता प्रदान कर बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन के प्रति जागरूक बनाया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का आरोप... ममता बनर्जी से सार्वजनिक माफी की मांग

- अंतिम समय में बदलकर बागडोगरा के गोसाईनपुर जैसे छोटे और दुर्गम स्थान पर क्यों किया गया
- भारत के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं।

रायपुर। संवाददाता

नीलकंठ टेकाम ने पश्चिम बंगाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान को लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफबताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति के स्वागत और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक टेकाम ने कहा कि देश की प्रथम नागरिक के दौरे के दौरान न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न ही राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री स्वागत के लिए उपस्थित थे। उन्होंने इसे राष्ट्रपति पद और संविधान का अपमान बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी को राष्ट्रपति, पूरे आदिवासी समाज और देश की महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। टेकाम ने यह भी सवाल उठाया कि पहले से तय सिलीगुड़ी के बिधाननगर जैसे सुलभ स्थल

को अंतिम समय में बदलकर बागडोगरा के गोसाईनपुर जैसे छोटे और दुर्गम स्थान पर क्यों किया गया। उनके अनुसार, इससे हजारों आदिवासी लोग राष्ट्रपति के संबोधन में शामिल होने से वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं, ऐसे में उनका सम्मान पूरे देश का सम्मान है। टेकाम ने कांग्रेस नेताओं द्वारा पूर्व में राष्ट्रपति के संबंध में की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह संवैधानिक पदों के प्रति असम्मानजनक रवैया दर्शाता है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आदिवासी स्वास्थ्य परंपराएं एवं औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन से देशभर के आदिवासी समाज में आक्रोश है। मरकाम ने घोषणा की कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तत्वावधान में 11 मार्च तक देशभर के जिलों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया जाएगा।

बस्तर और सरगुजा में औषधीय पौधों की योजनाओं का होगा विस्तारः विकास मरकाम

- छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की समीक्षा बैठक सम्पन्न

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की समीक्षा बैठक का आयोजन 12 मार्च को बोर्ड कार्यालय के सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम ने की। बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम ने कहा कि वन मंत्री श्री केदार कश्यप के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि बोर्ड और शासन की योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभाग में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने स्थानीय वैद्यों के स्थायी पंजीकरण के लिए भी आवश्यक प्रयास करने को कहा। बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला ने बैठक में कहा कि औषधीय पौधों का क्षेत्र अपार संभावनाओं से भरा है। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि बस्तर औषधीय पौधों के माध्यम से दुनिया के समृद्ध क्षेत्रों में शामिल हो। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जे.ए.सी.एस. राव ने बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं और गतिविधियों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों का रोपण, औषधीय पौधों की खेती (कृषिकरण) तथा विभिन्न नवाचार कार्यों की जानकारी दी गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जे.ए.सी.एस. राव ने आश्वस्त किया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार जल्द ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर बस्तर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने का कार्य शुरू किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में बस्तर क्षेत्र में पहले से लगाए गए पाम और नीलगिरी के प्लांटेशन में औषधीय पौधों की मल्टी-क्रॉपिंग के माध्यम से कार्य किया जाएगा। बैठक में नारायण संकल्प फाउंडेशन रायपुर की श्रीमती सीमा गुप्ता, एन.डी. मेमोरियल फाउंडेशन दुर्ग के श्री शालीभद्र मुथा, क्रिस्टल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी की श्रीमती रीनू छाबड़ा सहित बोर्ड की योजनाओं से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा बोर्ड के तकनीकी सलाहकार और कर्मचारी भी बैठक में शामिल हुए।

महतारी वंदन योजना से मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण की पहचान

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेश की लाखों माताओं-बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन रही है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिलने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। यह योजना महिलाओं की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में

सहायक सिद्ध हो रही है और परिवार पर उनकी आर्थिक निर्भरता को भी कम कर रही है। योजना से मिलने वाली यह सहायता राशि महिलाओं में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के शहरी क्षेत्र बुधवारी निवासी श्रीमती हेमलता साहू की कहानी भी प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है। श्रीमती साहू बताती हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है और कई बार आवश्यक जरूरतों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ जाती थी। ऐसे समय में महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि ने उन्हें काफी सहारा दिया है। अब उन्हें अपनी व्यक्तिगत जरूरतों या बच्चों की छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उन्होंने बताया कि वे वर्तमान में अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे योजना से प्राप्त राशि से अपने मोबाइल का रिचार्ज कर अध्ययन जारी रख रही हैं।

महतारी वंदन योजना से मिली नई राह, सिलाई कार्य से आत्मनिर्भर बनीं श्रीमती निहारिका

रायपुर। राज्य शासन की महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस योजना की सहायता से अवधिया पारा, पुरानी बस्ती निवासी श्रीमती निहारिका अवधिया ने सिलाई कार्य शुरू कर न केवल आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, बल्कि अपने परिवार के लिए स्थायी आय का साधन भी तैयार किया है।महतारी वंदन योजना के तहत श्रीमती निहारिका अवधिया को प्रतिमाह एक हजार रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इससे उन्होंने सिलाई मशीन के माध्यम से छोटा सा व्यवसाय प्रारंभ किया और धीरे-धीरे इसे अपने जीवनयापन का आधार बना लिया।पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में मैनुअल स्केवेंजर्स हेतु राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति की बैठक संपन्न

राज्य में हाथ से मैला उठाने की प्रथा (मैनुअल स्केवेंजर्स) का हुआ उन्मूलन

रायपुर/ संवाददाता

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ शासन के अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति की बैठक मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में भारसाधक सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री बसव राजू, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग डॉ. सारांश मित्तर, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री वी.पी. तिर्की, संयुक्त सचिव श्री अनुपम त्रिवेदी, अपर संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग श्री एन. बुलीवाल, द.पू.म.रे. से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक श्री रणजीत सुमन, सहायक निदेशक, जनगणना निदेशालय श्री

एम.के. महलांगे, एनजीओ से श्रीमती सुनिता कुर्रे, समुदाय की महिला एवं पुरुष प्रतिनिधि क्रमशः श्रीमती उत्तरा प्रहरे एवं श्री राजपाल कसेर सहित विभाग के अपर संचालक श्री जितेन्द्र गुप्ता, उपायुक्त श्री विश्वनाथ रेडडी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि शासन द्वारा राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति के पुनर्गठन के बाद यह पहली बैठक है उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में गाईडलाइन अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में मैनुअल स्केवेंजर्स रिसर्वे करवाया गया जिसमें सभी जिला कलेक्टर द्वारा मैनुअल स्केवेंजर्स मुक्त का प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि प्रदेश के लिए बहुत ही सम्मान एवं गौरव का क्षण है। इस जानकारी को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जबरन/दबावपूर्वक मैनुअल स्केवेंजर्स का कार्य करवाने वाले व्यक्तियों हेतु दंड का भी प्रावधान है, जिसमें एक वर्ष का कारावास अथवा पचास हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा मानवीय मूल्यों एवं संविधान द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों के विपरीत है। समाज में हर व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उन्होंने मैनुअल स्केवेंजर्स प्रथा के उन्मूलन की दिशा में सराहनीय प्रयास हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा अन्य सहयोगी विभागों/संस्थानों के समन्वित प्रयास की भी सराहना की। बैठक में वर्ष 2019 में आयोजित पूर्व बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध और उनके पुनर्वास नियम, 2013 के अंतर्गत नगर पालिकाओं एवं अन्य विभागों से प्राप्त जिलों की पुनर्सर्वेक्षण रिपोर्ट पर राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति द्वारा चर्चा की गई एवं भारत सरकार को रिपोर्ट प्रेषित किए जाने हेतु अनुमोदन किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र एवं टाउनशिप में कार्य करने वाले मजदूर वर्ग हेतु स्वच्छ शौचालय बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा प्रत्येक जनपद पंचायत क्षेत्र में सीवरेज डंपिंग के लिए एक से दो गाड़ियों की उपलब्धता पर बल दिया। साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां पर अभी तक स्वच्छ शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है वहां तत्काल गैप फिलिंग किए जाने के निर्देश दिए।

संपादकीय

जंग की आंच बाजार तक, तेल संकट

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के साझा हमले के बाद जिस बात का डर था, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। यानी जो देश इस जंग में शामिल नहीं हैं, उन तक भी इसकी आंच पहुंचनी शुरू हो चुकी है। जब दो या अधिक देशों के बीच युद्ध का मोर्चा खुलता है, तो उसका असर सिर्फ इस रूप में सामने नहीं आता कि एक-दूसरे पर किए गए हमले के नतीजे में जानमाल की व्यापक क्षति होती है। बल्कि जंग के लंबा खिंचने पर कई स्तरों पर जरूरी सामग्री की आपूर्ति बाधित होती है और नतीजतन बाजार में लगभग सभी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है।ईरान पर इजरायल और अमेरिका के साझा हमले के बाद जिस बात का डर था, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। यानी जो देश इस जंग में शामिल नहीं हैं, उन तक भी इसकी आंच पहुंचनी शुरू हो चुकी है। हाल ही में भारत के शेयर बाजार पर भी इसका असर देखा गया, जहां बड़ी गिरावट की वजह से निवेशकों को लगभग उन्नीस लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।चूंकि युद्ध की तीव्रता में फिलहाल कोई नरमी नहीं देखी जा रही है, इसलिए यह स्थिति अभी कायम रहने की आशंका है। मगर इससे इतर अब युद्ध का असर देश के आम लोगों के घर के दरवाजे तक पहुंचना शुरू हो चुका है। मसलन, रसोई गैस की कीमत में साठ रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है।कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की वजह से भारत सहित अन्य कई देशों को नए रास्तों की ओर देखना पड़ रहा है। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों के सौ डालर प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार के इस रुख का असर कहां तक जा सकता है और अगर युद्ध लंबा खिंचा, तो वैसे देशों में कैसी मुश्किल पैदा होगी, जहां की अर्थव्यवस्था और जीवनयापन का एक बड़ा हिस्सा बाहर से आपूर्ति पर निर्भर है।इजरायली हमले के बाद प्रतिक्रिया में ईरान ने जो रुख अख्तियार किया है, उससे पहले ही कई मुख्य तेल उत्पादक देशों में असुरक्षा का माहौल है। फिर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के रास्ते को ईरान ने जिस तरह बाधित कर दिया है, उससे दुनिया के एक बड़े हिस्से में तेल की आपूर्ति प्रभावित होगी।होर्मुज की नाकाबंदी की वजह से उस इलाके में फंसे जहाजों को लंबा रास्ता तय करना होगा। भारत के सामने ही स्थिति यह है कि इसके पास अगले छह से आठ हफ्ते का तेल भंडार है। स्वाभाविक ही भारत को अब तेल के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोतों की ओर देखना होगा।राहत की बात यह है कि एक ओर रूस ने भारत को तेल बेचने की पेशकश की, तो दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस मसले पर नरम रुख अपनाया है। इसके बावजूद पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध का असर केवल वैश्विक स्तर पर तेल और गैस के बाजारों पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि तनाव में बढ़ोतरी कई बड़े उद्योगों के लिए भी चिंता का कारण बन रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी बाधित हो रही है।खासतौर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल आना और इसका असर बाजार में अन्य लगभग सभी सामान पर पड़ना तय माना जा रहा है। दरअसल, इसके समांतर माल ढुलाई के महंगा होने की वजह से सब्जियों से लेकर दूसरी कई जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ेंगे।निश्चित रूप से इससे प्रभावित देशों को अपने स्तर पर विकल्प और समाधान निकालने की जरूरत है। मगर सवाल है कि क्या युद्ध में शामिल देशों को इस बात की फिक्र है कि उनकी वजह से दुनिया भर में आम लोगों के सामने अपनी अनिवार्य जरूरतें पूरी करने के लिए जद्दोजहद के कितने मोर्चे खुल गए हैं।

नये युग की समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आतंकवाद, गरीबी और डिजिटल असमानता भी महिलाओं के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं। यदि इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दशकों में करोड़ों महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी की ओर धकेली जा सकती हैं। मानव सभ्यता के विकास की कथा में यदि किसी शक्ति ने सबसे अधिक सृजन किया है, तो वह नारी शक्ति है। वह जीवन की जननी है, संस्कृति की वाहक है और समाज की संवेदनशील आत्मा है। भारतीय परंपरा ने नारी को केवल एक सामाजिक भूमिका तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे 'माता' के रूप में सर्वोच्च आदर दिया।

नारी शक्ति का नया युग और वास्तविक चुनौतियां

(ललित गर्ग)

'मातृदेवो भवः' की वाणी से लेकर 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' की घोषणा तक हमारी संस्कृति में नारी के प्रति श्रद्धा का अद्वितीय भाव दिखाई देता है। यही कारण है कि भारत में धरती, गौ और मातृभूमि तक को 'माता' कहकर संबोधित किया गया। किन्तु विडम्बना यह है कि जिस समाज ने नारी को देवी का दर्जा दिया, उसी समाज में आज भी नारी असुरक्षा, भेदभाव और हिंसा का सामना कर रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 हमें केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं देता, बल्कि यह अवसर देता है कि हम नारी की वास्तविक स्थिति का गंभीर आत्ममंथन करें। विश्व स्तर पर किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि नारी की स्थिति में प्रगति अवश्य हुई है, किन्तु समानता, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की यात्रा अभी लंबी है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में लैंगिक समानता का लगभग 68.8 प्रतिशत अंतर ही समाप्त हो पाया है, अर्थात् अभी भी लगभग एक तिहाई अंतर शेष है। आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में यह अंतर सबसे अधिक है, जहां समानता केवल लगभग 61 प्रतिशत तक ही पहुँची है।

वर्ल्ड इकनोमिक फोरम कि स्थिति बताती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो महिलाएँ लगभग बराबरी के स्तर तक पहुँच गई हैं, परंतु आर्थिक अवसरों और राजनीतिक नेतृत्व में अभी भी उनकी भागीदारी सीमित है। वैश्विक स्तर पर महिलाएँ कुल कार्यबल का लगभग 42 प्रतिशत ही हैं और शीर्ष प्रबंधकीय पदों पर उनकी हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई के आसपास है। भारत में भी स्थिति मिश्रित है। एक ओर भारतीय महिलाएँ अंतरिक्ष, विज्ञान, सेना, राजनीति और प्रशासन में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर श्रम बाजार में उनकी भागीदारी अभी भी कम है। हाल के आँकड़ों के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर लगभग 32 प्रतिशत है और बड़ी संख्या में महिलाएँ घरेलू दायित्वों के कारण रोजगार से बाहर रहती हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के यह आँकड़े केवल संख्या नहीं हैं, यह समाज की संरचना, सोच और अवसरों की असमानता को उजागर करते है। आज दुनिया के अनेक देशों में महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी और उद्योगपति के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। भारत में भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक और फाइटर पायलट के रूप में महिलाओं की उपस्थिति इस परिवर्तन का प्रमाण बनी है और बन रही है। किंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि दुनिया में अभी भी केवल सीमित देशों में ही महिलाएँ सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर हैं और समान वेतन का प्रश्न अभी भी अधूरा है। कई अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में औसतन कम वेतन मिलता है। एक और चिंताजनक तथ्य यह है कि संघर्ष, युद्ध और संकट की स्थितियों का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। हाल के वैश्विक अध्ययनों के अनुसार 2024 में लगभग 67 करोड़ महिलाएँ ऐसे क्षेत्रों में रह रही थीं जो किसी न किसी

प्रकार के हिंसक संघर्ष से प्रभावित थे।

नये युग की समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आतंकवाद, गरीबी और डिजिटल असमानता भी महिलाओं के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं। यदि इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दशकों में करोड़ों महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी की ओर धकेली जा सकती हैं। इतिहास के पन्ने यह भी बताते हैं कि जब-जब समाज संकट में पड़ा, तब-तब नारी शक्ति ने असाधारण साहस का परिचय दिया। स्वतंत्रता संग्राम में रानी चेनम्मा, बेगम हजरत महल, रानी अवन्तीबाई, सरोजिनी नायडू और दुर्गा भाभी जैसी वीरांगनाओं ने यह सिद्ध किया कि नारी केवल करुणा की प्रतिमा नहीं, बल्कि संघर्ष और साहस की भी प्रतीक है। लेकिन इतिहास के इन गौरवपूर्ण अध्यायों के बावजूद सामाजिक वास्तविकता कई बार पीड़ादायक दिखाई देती है। दहेज, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और यौन अपराध आज भी दुनिया के अनेक समाजों में मौजूद है। यह केवल कानून का नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता का प्रश्न है। दरअसल नारी समस्या का मूल कारण केवल बाहरी संरचनाएँ नहीं है, बल्कि वह सोच है जिसने सदियों तक नारी को 'कमजोर' मानकर उसकी क्षमता को सीमित करने का प्रयास किया।

जब समाज नारी को केवल भूमिका से जोड़ता है, व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, तभी असमानता जन्म लेती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का वैश्विक संदेश भी इसी दिशा में संकेत करता है- ''सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, न्याय और वास्तविक कार्रवाई।'' यह संदेश हमें याद दिलाता है कि आज भी दुनिया में महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार पूरी तरह प्राप्त नहीं हैं और औसतन उन्हें पुरुषों के मुकाबले लगभग 64 प्रतिशत ही कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ कि यह स्थिति हमें सोचने के लिए बाध्य करती है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन कानूनों को सामाजिक चेतना में बदलना भी आवश्यक है। नारी सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ केवल अधिकार देना नहीं है, बल्कि अवसर, सम्मान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक भागीदारी, ये पाँच स्तंभ नारी सशक्तिकरण की वास्तविक नींव हैं। परंतु इस परिवर्तन की शुरुआत घर से ही होगी। यदि परिवार में बेटी और बेटे को समान अवसर मिलते हैं, यदि शिक्षा में भेदभाव समाप्त होता है, यदि विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाज स्वयं अस्वीकार करता है, तभी नारी की वास्तविक मुक्ति संभव है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उल्लेखनीय कदम उठाये हैं। चाहे उज्ज्वला योजना के द्वारा उन्हें गैस सिलिंडर दिलाना हो, गावों में घरों और शौचालय का निर्माण हो या नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पास कराना। आज दुनिया के सभी देश इस बात को मान रहे है की मोदी के नेतृत्व में भारत की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। खेल जगत से लेकर मनोरंजन जगत तक और राजनीति से लेकर सैन्य व रक्षा तक में महिलाएं बड़ी भूमिका में हैं। बात भारतीय या अभारतीय नारी की नहीं, बल्कि उसके प्रति दृष्टिकोण की है। आवश्यकता इस दृष्टिकोण को बदलने की है, जरूरत सम्पूर्ण विश्व में नारी के प्रति उपेक्षा एवं प्रताड़ना को समाप्त करने की है। इस दिवस की सार्थकता तभी है जब महिलाओं को विकास में सहभागी ही न बनाये बल्कि उनके अस्तित्व एवं अस्मिता को नौंचने की वीभत्सताओं एवं त्रासदियों पर विराम लगे, ऐसा वातावरण बनाये।

नारी को भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। इतिहास गवाह है कि जब नारी ने अपने आत्मबल को पहचाना है, तब समाज की दिशा बदल गई है। शिक्षा और आत्मविश्वास नारी के लिए वही भूमिका निभाते हैं जो प्रकाश अंधकार के लिए करता है। आज की नारी केवल अधिकारों की मांग करने वाली नहीं, बल्कि परिवर्तन की निर्माता है। वह विज्ञान में शोध कर रही है, आकाश में विमान उड़ा रही है, संसद में कानून बना रही है, और समाज में नेतृत्व कर रही है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नारी सम्मान का प्रश्न केवल महिलाओं का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सभ्यता का प्रश्न है। जिस समाज में नारी सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर होती है, वही समाज वास्तव में विकसित और मानवीय कहलाता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का वास्तविक संदेश यही है कि नारी को सम्मान देने का कार्य केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि पूरे वर्ष की सामाजिक चेतना होना चाहिए। जब समाज यह स्वीकार कर लेगा कि नारी केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि भविष्य की निर्माता है, तब वह दिन दूर नहीं होगा जब 'नारी सशक्तिकरण' शब्द की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी-क्योंकि नारी स्वाभाविक रूप से सशक्त होगी और तब शायद दुनिया सचमुच उस आदर्श को जी पाएगी, जिसे भारतीय संस्कृति ने हजारों वर्ष पहले कहा था-यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।लेखक, पत्रकार, स्तंभकार है)। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच खाने का संकट हो सकता है पैदा, होर्मुज इफेक्ट से कई देश होंगे प्रभावित

(संजीव कुमार)

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के चलते पश्चिम एशिया के हालात बिगड़ सकते हैं। इस युद्ध का असर तेल और गैस आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। कई देशों को खाद्य

असुरक्षा और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन और रूस युद्ध के समय भी स्थिति बिगड़ी थी।

ईरान-इजरायल युद्ध के चलते पश्चिम एशिया के हालात की वजह से तेल और गैस आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। इसका नतीजा मार्केट पर दिखने लगा है। लेकिन, इसके बीच एक और संकट गहरा रहा है - उर्वरक आपूर्ति में कमी। अगर यह बाधा लंबे समय तक जारी रहती है तो दुनिया को खाद्य असुरक्षा और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है।

होर्मुज इफेक्ट- पश्चिम एशिया दुनिया का एक बड़ा उर्वरक उत्पादक क्षेत्र है। वैश्विक यूरिया निर्यात का लगभग 35व होर्मुज स्टेट से होकर गुजरता है। इसी रास्ते से दुनिया का 45व सल्फर भी ट्रांसपोर्ट होता है। यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है, जिसकी वजह से दुनिया का करीब आधा अनाज पैदा होता है। होर्मुज पर ईरान की पहरेदारी के चलते शिपमेंट का आना-जाना बंद है और हर बीतते दिन के साथ सप्लाई चेन टूट रही है। स्थिति ज्यादा गंभीर। करीब 4 साल पहले, जब यूक्रेन और रूस युद्ध शुरू हुआ था, तब भी इसी तरह की सिचुएशन बनी थी। उस वक्त दो बड़े झटके लगे थे - गेहूं की आपूर्ति में कमी और फर्टिलाइजर्स की कीमतों में तेज उछाल। यूक्रेन और रूस मिलकर गेहूं का करीब 30व ग्लोबल एक्सपोर्ट करते है, जिस पर उस समय एकदम से रोक लग गई थी। हालांकि तब जल्द ही रूस से दोनों चीजों का निर्यात जारी रहा। वहीं, भारत जैसे देशों ने गेहूं निर्यात बढ़ा दिया। लेकिन, इस बार सीधे समुद्री मार्ग बाधित होने से स्थिति दूसरी है। प्रॉडक्शन रोका। ईरान ने जिस तरह से दूसरे अरब देशों में मौजूद फैसिलिटीज को निशाना बनाया है, उससे भी असर पड़ा है। समुद्र के रास्ते होने वाले यूरिया के कुल व्यापार में क्वाटर एनर्जी की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत है। इसके एक कॉम्प्लेक्स पर दो दिन पहले ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने सल्फर, अमोनिया और यूरिया का प्रॉडक्शन रोक दिया है। ईरान और सऊदी अरब की सप्लाई भी प्रभावित हुई है।

गैस में कमी- फर्टिलाइजर मार्केट शुरू से बेहद संवेदनशील रहा है। चीन जैसे मुल्क अपनी जरूरत को देखते हुए ग्लोबल सप्लाई को प्रभावित करते हैं। नैचुरल गैस भी बड़ा फैक्टर है, जिसकी जरूरत फर्टिलाइजर प्रॉडक्शन में पड़ती है और जिसमें कमी आई है।

फसल पर असर। भारत ने पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच रेकॉर्ड 70 लाख टन यूरिया आयात किया था। देश अपनी जरूरत का करीब 40 प्रतिशत फर्टिलाइजर पश्चिम एशिया से मंगाता है, यानी उसके लिए स्थिति ज्यादा गंभीर है। अगर किसानों को समय से उर्वरक नहीं मिले, तो असर पहली फसल के साथ ही नजर आने लगेगा।

मोदी सरकार ने कई राज्यों में राज्यपाल पद पर फेरबदल कर दिये बड़े सियासी संकेत

तमिल नाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को वहां का नया राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले वह केरल में राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। चुनावी माहौल को देखते हुए इस नियुक्ति को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल तथा उपराज्यपालों की नई नियुक्तियों की घोषणा की। इस फैसले को व्यापक प्रशासनिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस बदलाव के तहत पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और लद्दाख सहित कई स्थानों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।सबसे प्रमुख बदलाव तमिल नाडु के राज्यपाल आरएन रवि के स्थानांतरण के रूप में सामने आया है। उन्हें अब पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

(नीरज कुमार दुबे)

वह सीवी आनंद बोस का स्थान लेंगे, जिन्होंने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस पिछले साढ़े तीन वर्ष से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा।तमिल नाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को वहां का नया राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले वह केरल में राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। चुनावी माहौल को देखते हुए इस नियुक्ति को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।दिल्ली और लद्दाख में भी अहम बदलाव हुए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। संधू लंबे समय तक कूटनीतिक सेवा में रहे हैं और विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी राज्यपाल बदले गए हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को अब तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं तेलंगाना के राज्यपाल रहे जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में भी नई नियुक्ति की गई है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। सेना में लंबे अनुभव वाले हसनैन सुरक्षा और रणनीति के मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान की जगह ली है।इस फेरबदल में हिमाचल प्रदेश के लिए भी नई नियुक्ति की गई है। लद्दाख के उपराज्यपाल रहे कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। कविंदर गुप्ता ने गुरुवार को लद्दाख के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल हालांकि काफी चर्चा में रहा। हम आपको याद दिला दें कि कविंदर गुप्ता को जुलाई 2025 में लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान 24

सितंबर 2025 को लेह शहर में हिंसक घटना हुई थी। उस दिन क्षेत्र को संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया था। हालात बिगड़ने पर पुलिस की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें करगिल युद्ध का एक पूर्व सैनिक भी शामिल था। इस घटना ने देश भर में व्यापक चर्चा को जन्म दिया था।तमिल नाडु में आर एन रवि और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार के बीच संबंध भी काफी तनावपूर्ण रहे। सत्तारुढ़ डीएमके ने कई बार आरोप लगाया कि राज्यपाल निर्वाचित सरकार के समानांतर राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। राज्यपाल रवि ने कई विधेयकों को मंजूरी देने में देर की थी। इसके बाद अप्रैल 2025 में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और दस विधेयकों को प्रभावी रूप से स्वीकृत मान लिया गया।राज्यपाल रवि कई बार विधानसभा में सरकार के तैयार भाषण को पढ़े बिना ही बाहर चले गए या फिर अपने विचारों के अनुसार भाषण में बदलाव किया। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि निर्णय उन पर होता तो वे नीट से छूट देने वाले विधेयक को कभी मंजूरी नहीं देते। इन घटनाओं के कारण राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रही।आरएन रवि का प्रशासनिक और सुरक्षा क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं और खुफिया ब्यूरो में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2014 से 2021 के बीच वे नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र सरकार के वार्ताकार भी रहे थे। उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर आरएन रवि की नियुक्ति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की खबर से वे चकित और चिंतित हैं।ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार से इस बारे में पहले कोई परामर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह स्थापित परंपरा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक हितों के कारण यह कदम उठाया गया हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो यह संविधान की भावना और देश की संघीय संरचना के लिए चिंताजनक स्थिति होगी। दो वर्ष पूरे करने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों और बदलावों का दौर शुरू हो चुका है। देखना होगा कि आने वाले समय में मोदी मंत्रिमंडल में क्या फेरबदल होते हैं या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

कलेक्टर अमित कुमार के निर्देशन में दोषियों पर गिरी प्रशासनिक गाज

प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्तीय अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई

सुकमा। जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर अमित कुमार के निर्देशन तथा जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठकुर के मार्गदर्शन में विकासखंड कोंटा की ग्राम पंचायत बंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासकीय राशि के उपयोग में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा जांच दल गठित कर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई गई। जांच में वित्तीय अनियमितताओं के तथ्य सामने आने के बाद प्रशासन ने संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत ग्राम पंचायत बंडा के तत्कालीन सचिव कृष्ण प्रकाश सिंह (निलंबित सचिव) को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं वर्तमान सचिव कु. गरिमा नाग तथा सचिव जी. लक्ष्मी को कार्य में लापरवाही न बरतने के निर्देश देते हुए अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के आवास मित्र, रोजगार सहायक तथा जनपद पंचायत कोंटा के आवास ऑपरेटर को भी पद से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही जनपद पंचायत कोंटा के ब्लॉक समन्वयक आवास को कलेक्टर द्वारा अंतिम चेतावनी जारी करते हुए भविष्य में किसी भीकार की लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कार्रवाई से पहले सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया था। तथ्यों के आधार पर ही यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों के अधिकारों का हनन करने या शासकीय राशि के दुरुपयोग में लिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी यदि किसी भी शासकीय कार्य में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पीएमश्री पोटा केबिन देवगांव में वार्षिक उत्सव व कल्चरल एग्जीबिशन का भव्य आयोजन, विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

नारायणपुर। जिला नारायणपुर के पीएमश्री पोर्टा केबिन देवगांव में वार्षिक उत्सव एवं कल्चरल एग्जीबिशन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने लोकनृत्य, देशभक्ति गीत, नाटक, समूह नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने न केवल अपनी कला और रचनात्मकता का परिचय दिया, बल्कि दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही विद्यालय में कल्चरल एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न शैक्षणिक मॉडल, चार्ट और रचनात्मक सामग्री प्रदर्शित की गई। इन प्रदर्शनों के माध्यम से बच्चों की सृजनात्मक क्षमता और सीखने की लगन स्पष्ट रूप से देखने को मिली।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कुलेश्वर सलाम उपस्थित रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में ललित पोयाम, जिला मंत्री युवा मोर्चा शामिल हुए। अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों के प्रयासों की प्रशंसा की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि कुलेश्वर सलाम ने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी उतना ही महत्व है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, संस्कार और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी तथा विद्यालय की शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों की सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्राचार्य मोहन लाल साहू एवं संकुल प्राचार्य नीता देवांगन का विशेष योगदान रहा। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। और उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है।

219 बटालियन सीआरपीएफ ने किया सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन

कोंटा। आम जनता से मित्रता व सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से 219 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा समय-समय पर सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में 11 मार्च 2026 को कोंटा रेंज के डीआईजीपी राजेश पांडे के मार्गदर्शन तथा 219वीं बटालियन के कमांडेंट पार्थ सारथी घोष के निर्देशन में भेजी कैंप में सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में द्वितीय कमान अधिकारी अनुराग राज, सहायक कमांडेंट कानाराम चौधरी और सहायक कमांडेंट यश कुमार गौतम उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों में सुरक्षा का भाव पैदा करना, केंद्र और राज्य सरकार की विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना तथा ग्रामीणों और प्रशासन के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना रहा। कार्यक्रम में भेजी कैंप के आसपास के गांवों से करीब 250 ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान ग्रामीणों को साइकिल, मच्छरदानी, बर्तन, सौर लालटेन, महिलाओं को साड़ी, बुजुर्गों को कंबल व लुंगी, ग्रामीणों को चप्पल, युवाओं के लिए खेल सामग्री और बच्चों के लिए पढ़ाई से संबंधित सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. मोहम्मद इब्राहिम ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्होंने गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों जैसे लू लगना, निर्जलीकरण, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड से बचाव के उपाय बताए तथा अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी। साथ ही बीमार ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार देकर दवाइयां वितरित की गईं और स्वच्छ जल व साफ-सफाई के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई।

भाजपा सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती : बीजापुर कांग्रेस ने दुर्ग के समोदा गांव मामले पर जिला भाजपा कार्यालय का किया घेराव

बीजापुर । जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने गुरुवार को जिला मुख्यालय बीजापुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव कर प्रदेश के दुर्ग जिले के समोसा गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा बड़े पैमाने पर अफीम की खेती किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर ने कहा कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा लगभग 10 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती किये जाने का मामला उजागर होने से स्पष्ट हो गया है कि, राज्य की भाजपा सरकार नशे के कारोबार को संरक्षण देकर प्रदेश के युवाओं को नशे की ओर धकेलने का प्रयास कर रही है। पिछले दो वर्षों में शराब, गांजा, अफीम, हिरोईन जैसे नशे के कारण प्रदेश की युवा पीढ़ी में नशे की लत महामारी का रूप ले चुकी है। चंद पैसों के लिये सत्तासीन लोग नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के बजाय संरक्षण दे रहे हैं। लालू राठौर ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में नशे को कारोबार को संरक्षण दे रही है जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर धरना प्रदर्शन कर भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया है। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पीसीसी सदस्य शंकर कुडियम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतीय उद्दे, लच्छू राम मौर्य, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बसंत टाटी, महामंत्री सुखदेव नाग, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अवलम, रमेश यालम, रमेश पमभोई, अशोक माड़े, नकुल ठाकुर, मंगल राना, मनोज यालम, पुरुषोत्तम सल्लूर, जनपद अध्यक्ष सोनू पोटम, उपाध्यक्ष दिनेश पुजारी, महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष संजना चौहान, महिला प्रदेश कांग्रेस सचिव शेख रजिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरिता चापा, सोमारू राम कश्यप, जनपद सदस्य अनिता तेलम, पूर्व जनपद सदस्य रेंगा नागेश, केजी सत्यम, अंकित सिंग, सुरेश सोढ़ी सहित महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवादल और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

नशे के कारोबार और अफीम खेती के विरोध में कांग्रेस का भाजपा कार्यालय घेराव

सुकमा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कथित रूप से बढ़ रहे नशे के अवैध कारोबार और अफीम की खेती के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को जिला मुख्यालय सुकमा में भाजपा कार्यालय का घेराव किया। यह प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश कवासी लखमा के नेतृत्व में आयोजित इस घेराव कार्यक्रम में जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, पंच-सरपंच, जिला पंचायत प्रतिनिधि, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, नगर कांग्रेस तथा नगर पालिका परिषद के पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं के संरक्षण में अफीम की खेती और नशे का अवैध कारोबार बढ़ रहा है। इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी लखमा ने कहा कि पहले नशाबंदी का विरोध करने वाले भाजपा कार्यकर्ता आज स्वयं अफीम की खेती में लिप्त बताए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिससे प्रदेश में अपराध और अप्रिय घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी धान का कटोरा कहलाता था, लेकिन आज प्रदेश को अफीम का कटोरा बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसे मामलों का लगातार विरोध करती रही है और यदि जल्द ही नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ और उग्र आंदोलन किया जाएगा।

वनों की आग से सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने ली शपथ

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत नारायणपुर वन मंडल नारायणपुर द्वारा जिले के समस्त वन परिक्षेत्रों में वनों को आग से बचने एवं वन्य जीव संरक्षण की दिशा में लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अबूझमाड़ के दूरस्थ वन परिक्षेत्र पश्चिम सोनपुर के ग्राम पंचायत कोंगे एवं ग्राम बैंस टोला, ग्राम पंचायत पांगुड में नारायणपुर वन मंडलाधिकारी वेंकटेश एम जी के मार्गदर्शन में लोक कला मंच के माध्यम से वनो को आग से बचाव हेतु जन जागरुकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें ग्रामीणों को वनो को आग से होने वाले नुकसान-वन्य प्राणियों एवं छोटे औषधि पौधें का आग से जल जाना, आग की वजह से हर साल निकलने वाले नए पौधे का जल जाना, वन के सूखे पत्ते जो गलके खाद बनते है उनका जलना, जलाऊ एवं निस्तार में कमी होना, पक्षियों के घोंसले का नष्ट होना, वन्य प्राणियों की अकाल मौत, बारिश में कमी होना के बारे में बताया गया। इसी प्रकार महुआ संग्रहण समय महिलाओं के द्वारा आग लगाना, होली त्योहार मे आग लगाना, तेंदूपत्ता साख कर्तन, साल बीज संग्रहण समय आग लगाना,जान बूझकर जंगल में आग लगाना, जलता बीड़ी सिगरेट जंगल में डाल देना जैसे बहुत से कारण है वनों में आग लगने के। लोककला, नृत्य एवं नाटक के माध्यम से वनों में लगने वाले आग को स्वयं ग्रामीण द्वारा बुझाने एवं आग नहीं लगाने की समझाइश दी गई। इस अवसर पर उपस्थित वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों द्वारा जंगल की रक्षा करने एवं जंगल को आग से बचाने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पांगुड़ की सरपंच धनाय उसेंडी एवं वरिष्ठ ग्रामीण कादे राम ईसामी ने ग्रामीणों को संबोधित कर आग से वनों की रक्षा करने का भरोसा जताया। ग्रामीणों ने जंगल के विकास एवं सुरक्षा में सतत योगदान देने पर अपनी सहमती जतायी। इन कार्यक्रमों में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, अग्नि रोकथाम कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी, आसपास के ग्रामीण, ग्राम के पटेल, गायता,संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, अग्नि प्रहरी सहित ग्राम पंचायत कोंगे के कटिया राम धुव, बल्दू राम गोटा, माहरु राम ध्रुव, दासु नुरेटी, वक्के इसामी, मनकू नुरेटी, सुकलु कचलामी, कठिया नुरेटी,समरी? ध्रुव, रमी नूरेठी, जानको नुरेटी, ममता, सीता ध्रुव, कमला नुरेटी आदि उपस्थित थे इसी प्रकार ग्राम पंचायत पांगुड़ के दसरू राम उसेंडी,मेरिया पट्टावी,लिंगों मड्डामी,वार्ड पंच सुकलु मंडावी, चमरी मेड्डामी,सुमित्रा मंडावी,सेते उसेंडी,जुल्ले बाई,पांडरी मंडावी सहित बड़ी संख्या में नवयुवक एवं महिलाएं उपस्थित थी।

ईदवाया में सिविक एक्शन कार्यक्रम का सफल आयोजन

नारायणपुर। रोशन सिंह असवाल, कमांडेंट, 38वी वाहिनी, आईटीबीपी के कुशल मार्गदर्शन में 11 मार्च को सीओबी इदवाया, 38वी वाहिनी द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गाँव इदवाया, मालानार, कोरवाया एवं भटकुपारा के ग्रामवासियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, जिसमें स्कूल के बच्चे, ग्रामीण महिलाऐ, बुजुर्ग व नौजवान शामिल हुये। जिनको इस कार्यक्रम के तहत चप्पल, लोवर, कृषि से संबंधित औजार, पानी जग, शटल कॉक, वॉलीबॉल नेट एवं सोलर स्ट्रीट लाईट एसेसिरिज सहित इत्यादि दैनिक इस्तेमाल के सामानों का निःशुल्क वितरण किया गया। सिविक एक्शन प्रोग्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में ग्रामवासियों के साथ-साथ गाँव के संरपचों, सचिव, प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं अन्य गणमान्य सदस्यों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा की विदित है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों के उत्थान हेतु अनेक आर्थिक और सामाजिक कल्याणकारी योजनाये चलाई जा रही है और इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को सार्थक बनाने में स्थानीय प्रशासन के साथ सुरक्षा बल भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है, जिनके अथक प्रयासो से ही इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के साथ साथ क्षेत्र में ग्रामीणों को नशा मुक्ति हेतु प्रेरित किया गया साथ ही ग्रामीणों को स्वस्थ्य सेवा व अन्य प्रेरक कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना है। इस सिविक एक्शन प्रोग्राम को सफल बनाने में सीओबी इदवाया मे तैनात 38वी वाहिनी आईटीबीपी बल और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने बढ-चढ़कर भाग लिया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नालंदा परिसर के निर्माण के लिए नगर पालिका ने किया भूमि निरीक्षण

नारायणपुर। नगर पालिका नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत नालंदा परिसर का निर्माण किया जावेगा। उक्त निर्माण को लेकर नगर पालिका द्वारा भूमि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, उपाध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामचंद्र यादव, उप अभियंता बसंत कुंजाम तथा सभी वार्डों के पार्षदगण जयसवाल वह्, रीता मंडल, संगीता जैन, कीर्ति पोटाई, संतोष गोटा, संजय नंदी, कमलापति मिश्रा, नेहा कश्यप, विजय सलाम, रमशिला नाग,प्रवीण जैन, कौशल बघेल, गोविंद भोयर एवं हेमंत पात्र उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 4.41 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले नालंदा परिसर से शहर के युवाओ को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माहौल उपलब्ध होगा। जिससे नगर के युवा शासन, प्रशासन एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में चयनित होकर जन सेवा कर सकेंगे।

किरंदुल वार्ड क्रमांक 7 में दैनिक योग कक्षा का शुभारंभ

किरंदुल। किरंदुल के वार्ड क्रमांक 07, पुराना भट्टी पारा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपरी कक्ष में बैलाडीला योग समिति एवं पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार दैनिक योग कक्षा का शुभारंभ किया गया।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित रहे और योग के महत्व को समझते हुए नियमित अभ्यास का संकल्प लिया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद किरंदुल की अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह उपस्थित रहीं।इस अवसर पर बैलाडीला योग समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष अमृत टंडन,महासचिव जितेन्द्र गुप्ता,योग शिक्षक छबील साहू एवं योग कोच नरोत्तम ध्रुव उपस्थित रहें। सभी अतिथियों ने योग को स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया।

जिला स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन संपन्न

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रायपुर के तत्वावधान में जिला स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोंडागांव में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। यह संपूर्ण कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान के संरक्षण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के पांचों विकासखंडों से आए विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान भारतीय वैज्ञानिक डॉ. सी. वी. रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विद्यार्थियों और समाज में विज्ञान के प्रति रुचि, जागरूकता तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय विज्ञान में महिलाएं रू विकसित भारत के लिए उत्प्रेरक रखा गया है, जिसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निबंध लेखन, क्विज प्रतियोगिता तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी विद्यार्थियों ने विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन जिला समन्वयक धर्मेन्द्र चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में किया गया। क्विज प्रतियोगिता का संचालन क्विज मास्टर अंकित गुप्ता द्वारा रोचक एवं ज्ञानवर्धक शैली में किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्साहपूर्वक उत्तर दिया।

कलेक्टर के निर्देशन में शहर के चौक-चौराहों पर बनाए जा रहे स्पीड ब्रेकर

नारायणपुर। कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशन में नगर में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर के प्रमुख चौक-चौराहों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य वाहनों की गति को नियंत्रित कर सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता संजय चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के घड़ी चौक, हाई स्कूल के सामने तथा जिला अस्पताल के सामने पूर्व में बनाए गए स्पीड ब्रेकरों का मरम्मत एवं सुधार कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के मुख्य मार्गों और प्रमुख बाजार स्थलों के सामने भी नए स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में यह कार्य किया जा रहा है।

कोंडागांव में सभी दुकानों की मैपिंग का कार्य पूर्ण, व्यापारियों से ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अपील

कोण्डागांव। राज्य सरकार द्वारा बाजारों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे-बड़े बाजारों की मैपिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसी निर्देश के अनुपालन में नगर पालिका कोंडागांव द्वारा शहर की सभी दुकानों का सर्वे एवं मैपिंग कराया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा ट्रेड लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है, साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अब नगर क्षेत्र के सभी छोटे और बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। यह शुल्क शासन के गैजेट के अनुरूप वार्षिक आधार पर लिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

बरपाली में खेत के ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चोरी, किसान परेशान

कोरबा । जिले के कोरबा चांपा मुख्य मार्ग स्थित बरपाली गांव में चोरों ने एक किसान के खेत में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते हुए उसमें से कीमती सामान चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर चालू हालत में था, इसके बावजूद चोरों ने उसे खोलकर अंदर के महत्वपूर्ण पुर्जे निकाल लिए। जानकारी के अनुसार बरपाली निवासी किसान शिवांश खत्री के खेत में लगा ट्रांसफार्मर चोरों ने देर रात खोल दिया और उसमें से कीमती सामान निकालकर फरार हो गए। सुबह जब किसान खेत पहुंचे तो ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ और चोरी की जानकारी सामने आई। बरपाली क्षेत्र, जो उरगा थाना अंतर्गत आता है, में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी और भय का माहौल है। किसान शिवांश खत्री ने बताया कि उनके खेत में लगा ट्रांसफार्मर चालू हालत में था। देर रात अज्ञात चोरों ने उसे खोलकर अंदर के कीमती पुर्जे निकाल लिए, जिससे खेती के कामकाज में परेशानी होने लगी है। उन्होंने प्रशासन से चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना उरगा पुलिस को दे दी गई है। साथ ही विद्युत विभाग को भी जानकारी दे दी गई है, ताकि ट्रांसफार्मर की स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

सीआईएसएफके 57 वें स्थापना दिवस गेवरा लाइन में आयोजित

कोरबा। सीआईएसएफ के 57 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सीआईएसएफइकाई एसईसीएल, बिलासपुर के गेवरा लाइन में भव्य परेड, शस्त्र कौशल एवं योग प्रदर्शन के साथ साथ बलसदस्यों को शुभकामनाएं देने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सीआईएसएफ उपमहानिरीक्षक श्री निर्विकार और वरिष्ठ कमांडेंट डॉ. नागेंद्र कुमार झा के मार्गदर्शन में बड़ाखाना आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री रामगोपाल गर्ग, कोरबा कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, कोरबा पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, दर्री सीएसपी श्री विमल कुमार पाठक, श्री अरुण कुमार त्यागी महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा क्षेत्र, श्री एन के साहू महाप्रबंधक ऑपरेशन एसईसीएल गेवरा क्षेत्र और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उपस्थित होकर सीआईएसएफ के बल सदस्यों को बधाई दी और उनका उत्साहवर्धन किया। बिलासपुर रेंज के महानिरीक्षक ने सभी बल सदस्यों को बधाई दी और सीआईएसएफ की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए एक उत्कृष्ट बल की उपाधि प्रदान की। उन्होंने सीआईएसएफ की कार्यकुशलता का वर्णन करते हुए देश के विकास में योगदान की प्रशंसा की। इस अवसर पर देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक गीतों की प्रस्तुति द्वारा सीआईएसएफ के बल सदस्यों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। अंत में सीआईएसएफ उपमहानिरीक्षक श्री निर्विकार ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस प्रकार का आयोजन बल सदस्यों के मनोबल को बढ़ाने और उनमें अपने बल के प्रति विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक व्यापक कदम है।

अवैध व फर्जी बिजली कनेक्शन का पता लगाने चलेगा अभियान

कोरबा। जिले में अवैध व फर्जी बिजली कनेक्शन का पता लगाने 2 लाख उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी की जाएगी। मीटर रीडर ही घरों और संस्थानों में जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इससे लोगों को डिजिटल सेवाएं घर बैठे मिलेगी। ई-केवायसी का उद्देश्य डेटाबेस अपडेट करना, बिजली चोरी रोकना, सरकारी सब्सिडी का फायदा लाभार्थियों तक पहुंचाना है। उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप या एप के जरिए डिजिटल सेवा मिलेगी। अब तक एक ही कनेक्शन से कई जगह सुविधा लेने या बिजली चोरी की शिकायतें मिलती रही हैं। अब इस तरह की गड़बड़ियां ई-केवायसी से पकड़ में आएंगी। जिले में 2 लाख 8821 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें सिटी डिवीजन कोरबा के 69 हजार 609, ग्रामीण संभाग कोरबा के 65 हजार 314 और कटघोरा संभाग के 73 हजार 898 उपभोक्ता शामिल हैं। मीटर रीडर इनके घरों व संस्थानों में पहुंचकर ई-केवाईसी करेंगे। वहीं पुराने मीटर बदलकर उपभोक्ताओं के घरों व दुकानों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी जारी है।

शासकीय स्कूल में निशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर आयोजित

कोरिया। संचालनालय आयुष रायपुर के निर्देशानुसार एवं जिला आयुष अधिकारी के मार्गदर्शन में शासकीय प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला पुलिस लाइन बैकुंठपुर में आयुष विंग जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर द्वारा निशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्कूल के छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही ग्रीष्म ऋतु में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों, उनके लक्षण तथा बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। चिकित्सकों द्वारा बच्चों को स्वच्छता, हस्त प्रक्षालन की सही विधि, सुपोषण, दिनचर्या, रात्रिचर्या तथा संतुलित आहार के महत्व के बारे में भी बताया गया।

एसईसीएल सतर्कता की नज़र, 'प्रयास' का असर– 846 विधवा-परिजनों को मिला हक़

एसईसीएल मानव संसाधन विभाग-सीएमपीएफओ की संयुक्त पहल, 'प्रयास' शिविरों से क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया हुई तेज.......

बिलासपुर। एसईसीएल के सतर्कता विभाग की अगुआई में साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में पीएफ-पेंशन विभाग एवं कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के संयुक्त प्रयासों से अप्रैल 2025 से अब तक पीएफ एवं पेंशन के 846 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है। यह पहल विशेष रूप से दिवंगत कर्मियों की विधवाओं और आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा लाभ समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुई है। दिवंगत कर्मियों की विधवाओं और आश्रितों को राहत – इन मामलों में बड़ी संख्या मृत कर्मचारियों के आश्रितों, विशेषकर विधवा एवं बाल पेंशन से संबंधित मामलों की थी। ऐसे मामलों में विलंब से लाभ मिलने के कारण परिजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संवेदनशील विषय को गंभीरता से लेते हुए एसईसीएल के सतर्कता विभाग ने 5 अप्रैल 2025 को सीएमपीएफओ और प्रबंधन के साथ इस मुद्दे को औपचारिक रूप से उठाया तथा लंबित मामलों के शीघ्र और समयबद्ध निपटारे के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। संयुक्त बैठक और सतत निगरानी से तेज हुई प्रक्रिया – सतर्कता विभाग की पहल के बाद 22 अप्रैल 2025 को एसईसीएल प्रबंधन द्वारा सीएमपीएफओ तथा विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ एक तात्कालिक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबित मामलों की केस-वाइज समीक्षा की गई और उनके शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही पीएफ-पेंशन मामलों की

प्रगति पर सतत निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मासिक समीक्षा तंत्र भी शुरू किया गया। 'प्रयास' शिविरों से क्लेम सेटलमेंट में तेजी – मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सीएमपीएफओ की पहल पर प्रयास नामक विशेष अभियान के अंतर्गत एसईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में जुलाई 2025 से फरवरी 2026 के बीच कुल 9 पीएफ-पेंशन शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे सहायता प्रदान की गई तथा आवश्यक दस्तावेजों का मौके पर सत्यापन कर लंबित मामलों के समाधान की प्रक्रिया को तेज किया गया। इन समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप अप्रैल 2025 से अब तक प्रति माह औसतन लगभग 75 मामलों का निपटारा संभव हो पाया है। इस अभियान के चलते न केवल पुराने लंबित मामलों का तेजी से समाधान हुआ, बल्कि नए आने वाले मामलों के भी त्वरित निपटारे की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिससे कुल लंबित मामलों की संख्या न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है। रैंडम फोन कॉल के माध्यम से कर्मियों से लिया गया सीधा फीडबैक – प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन द्वारा पूर्व कर्मचारियों के आश्रितों से रैंडम फोन कॉल के माध्यम से सत्यापन किया गया तथा पेंशन भुगतान आदेशप्राप्त कर उनकी निगरानी भी की गई दिनों में मिला पेंशन आदेश, परिवार ने जताया आभार– इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया का प्रभाव इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि एसईसीएल मुख्यालय के स्वर्गीय कर्मचारी भारत भूषण की पत्नी श्रीमती विमला भूषण के विधवा पेंशन क्लेम का निपटारा मात्र 7 दिनों में कर दिया गया।

विधानसभा तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह की मांग पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने ग्राम विजयपुर को उप-तहसील बनाने की आधिकारिक घोषणा

उन्होंने बताया कि विजयपुर में 9 पटवारी हल्के और बेलपान के 8 पटवारी हल्के शामिल हैं

तखतपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए खुशखबरी, विधानसभा तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह की मांग पर राजस्व मंत्री ने ग्राम विजयपुर को उप-तहसील बनाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। सदन में उठी को मिली मंजूरी, सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक धर्मजीत सिंह ने राजस्व विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए क्षेत्र की इस पुरानी आवश्यकता को प्रमुखता से रखा। उन्होंने बताया कि विजयपुर में 9 पटवारी हल्के और बेलपान के 8 पटवारी हल्के शामिल हैं। इन दोनों राजस्व मंडलों को मिलाकर एक पूर्ण उप-तहसील बनाने की जरूरत थी। यहाँ वर्तमान में नायब तहसीलदार पहले से ही कार्यरत हैं, जिसे अब पूर्ण दर्जा प्रदान किया गया है। राजस्व मंत्री का निर्णय विधायक की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में घोषणा

की कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर को उप-तहसील का दर्जा दिया जाता है। जनता को होने वाले लाभ विजयपुर को उप-तहसील का दर्जा मिलने से स्थानीय ग्रामीणों को कई सहूलियतें मिलेंगी जिसमें राजस्व मामलों का निपटारा होगा अब ग्रामीणों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दस्तावेजों में आसानी होगी जैसे जाति, निवास प्रमाणपत्र और फौती जैसे कार्यों के लिए भटकना नहीं होगा। प्रशासनिक केंद्र बनने से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।

बिलासपुर नगर विधायक अमर अग्रवाल हुए शामिल, कुंदन पैलेस में आयोजित कार्यकर्ता होली मिलन समारोह में

बिलासपुर। कुंदन पैलेस में आयोजित कार्यकर्ता होली मिलन समारोह में नगर विधायक अमर अग्रवाल शामिल हुए। इस अवसर पर बिलासपुर के वरिष्ठ नेताओं, सभी मंडलों के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति से कुंदन पैलेस का मैदान होली के रंगों में सराबोर हो गया। इस मनोरम, उत्साहपूर्ण वातावरण में अमर अग्रवाल की उपस्थिति ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। फाग गीतों की मधुर धुनों के बीच आयोजित इस समारोह को उन्होंने अत्यंत आनंदमय बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि होली का यह पावन पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। ऐसे आयोजन संगठन को और अधिक सशक्त बनाते हैं तथा कार्यकर्ताओं के बीच आपसी आत्मीयता को बढ़ाते हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं देते हुए संगठन की मजबूती के लिए निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शराब के नशे में स्कूल पहुंचे दो शिक्षक निलंबित, डीईओ ने की कड़ी कार्रवाई

बिलासपुर। स्कूल में शराब के नशे में पहुंचने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए मस्तूरी विकासखंड के दो सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों मामलों में स्थानीय शिकायत, जांच और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह कार्रवाई की गई। पहला मामला ग्राम पंचायत जुनवानी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का है। 6 मार्च को ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि स्कूल निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान वहां पदस्थ सहायक शिक्षक संदीप रात्रे शराब के नशे में पाए गए। स्कूल के प्रधान पाठक ने भी बताया कि संदीप रात्रे अक्सर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहते हैं, जिससे स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित होती है। ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जनप्रतिनिधियों और स्कूल स्टाफ ने संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर इसे मस्तूरी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को सौंप दिया। बीईओ की जांच में भी शिकायत सही पाई गई। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने संदीप रात्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दर्रीघाट निर्धारित किया गया है। दूसरा मामला मस्तूरी ब्लॉक के पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला कुकुर्दीकला का है। यहां पदस्थ सहायक शिक्षक उत्तम कुमार कंवर के खिलाफ भी शराब पीकर स्कूल आने की शिकायत मिली थी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आधुनिक तकनीक का उपयोग : रायपुर मंडल में ओएचई निरीक्षण के लिए एआई-संचालित ड्रोन की तैनाती

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, परिचालन की सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा रेलवे विद्युत अवसंरचना की निगरानी और रखरखाव को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से युक्त ड्रोन तकनीक का उपयोग प्रारंभ किया गया है। रायपुर मंडल के विद्युत (टीआरडी) विभाग द्वारा ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) संरचनाओं के निरीक्षण के लिए अत्याधुनिक ड्रोन तैनात किए गए हैं। इस तकनीक के माध्यम से ऊँचाई से ओएचई संरचनाओं, फिटिंग्स तथा अन्य विद्युत अवसंरचनाओं का विस्तृत और सूक्ष्म निरीक्षण किया जा रहा है। ड्रोन द्वारा ऐसे कई स्थानों की निगरानी संभव हो पा रही है, जहाँ पारंपरिक मैनुअल निरीक्षण कठिन होता है या जहाँ छोटे तकनीकी दोषों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण होता है। ड्रोन से प्राप्त उच्च-गुणवत्ता वाले चित्रों और वीडियो का विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स की

सहायता से किया जा रहा है। एआई-आधारित विश्लेषण संभावित तकनीकी दोषों की पहचान तेज़ी और अधिक सटीकता के साथ करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके माध्यम से ओएचई के विभिन्न घटकों और फिटिंग्स की विस्तृत जाँच कम समय में संभव हो रही है, जिससे समय रहते आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दोषों की समय पर पहचान होने से संभावित बड़ी तकनीकी खराबियों या ब्रेकडाउन को रोका जा सकता है। इससे न केवल रेल परिचालन की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है, बल्कि ट्रेनों के सुचारू और निर्बाध संचालन में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आधुनिक तकनीकों को अपनाने की यह पहल रेलवे अवसंरचना की निगरानी, रखरखाव और सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एआई और ड्रोन तकनीक का यह समन्वय रेलवे परिचालन के आधुनिकीकरण के साथ-साथ संरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

श्रीरामभक्त प्रवीण झा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सौंपा अयोध्या यात्रा आमंत्रण पत्र...

■ नगर विधायक अमर अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर सीएम आवास में भेंट

बिलासपुर। रामनवमी के पावन अवसर पर बिलासपुर से अयोध्या धाम के लिए निकलने वाली 1008 रामभक्तों की निशुल्क यात्रा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच रही हैं, समाजसेवी एवं यात्रा संयोजक प्रवीण झा ने नगर विधायक अमर अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उन्हें इस पावन यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए यात्रा आयोजन की सराहना की और अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होने का हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। रामनवमी के अवसर पर आयोजित इस रामलला दर्शन यात्रा को लेकर बिलासपुर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले सिविल लाइन स्थित पुलिस मैदान में हुए पंजीयन के दौरान महज कुछ ही घंटों में 1008 सीटें भर जाने से रामभक्तों की अटूट आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला था। इसी उत्साह के बीच सोमवार को यात्रा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री से भेंट की। नगर विधायक अमर अग्रवाल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में यात्रा संयोजक प्रवीण झा और भाजपा युवा मोर्चा नेता रौशन सिंह भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री

को रामनवमी के अवसर पर आयोजित अयोध्या धाम की इस विशेष यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बिलासपुर आकर रामभक्तों को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम भारतीय संस्कृति, आदर्श और मर्यादा के प्रतीक हैं। अयोध्या धाम केवल एक तीर्थस्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती का भी प्रभु श्रीराम से गहरा आध्यात्मिक संबंध रहा है और रामभक्तों की ऐसी यात्राएं समाज में श्रद्धा, संस्कृति और एकता की भावना को और मजबूत करती हैं। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए जुटे सभी समिति सदस्यों की भूरी-भूरी प्रशंसा भी की। यात्रा समिति के सदस्य रौशन सिंह ने बताया कि रामनवमी से एक दिन पहले 25 मार्च को सुबह 11 बजे बिलासपुर के पुलिस मैदान से 1008 रामभक्तों का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना होगा। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और इसे लेकर तैयारियां भी तेजी से जारी हैं।

राजनीतिक नौटंकी कर रही कांग्रेस-रामचरित...

मनेन्द्रगढ़। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राम चरित द्विवेदी ने कांग्रेस द्वारा भाजपा जिला कार्यालय के घेराव किये जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित कदम है। जब प्रशासन अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रहा है। तब कांग्रेस का इस तरह विरोध करना कई सवाल खड़े करता है। द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही कानून के दायरे में रहकर की जा रही है ताकि अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके और समाज को नशे के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस कार्यवाही का विरोध करते हुए भाजपा कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, जो समझ से परे है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पहले यह स्पष्ट करे कि वह आखिर चाहती क्या है। क्या कांग्रेस अवैध अफीम की खेती करने वालों का समर्थन कर रही है? यदि प्रशासन कानून के तहत कार्यवाही कर रहा है तो उसका विरोध करना कहीं ना कहीं अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने जैसा प्रतीत होता है। भाजपा मीडिया प्रभारी ने आगे कहा कि कांग्रेस को यह भी स्पष्ट करना चाहिये की उनके नेता कवासी लखमा और चैतन्य बघेल इतने दिनों तक जेल में क्यों रहे।

आर्थराइटिस पेन को गठिया का दर्द भी कहा जाता है। जिसे कम करने के लिए कुछ चीजों का सेवन करना चाहिए। शोधों में इन फूड्स को दर्द और इंफ्लामेशन से छुटकारा दिलाने वाला पाया गया है।

जड़ से खत्म होगा गठिया का दर्द

बुढ़ापे के साथ जोड़ों का दर्द भी आना आम बात है। इस रोग को गठिया या आर्थराइटिस भी कहा जाता है। उम्र के साथ घुटनों, कोहनी आदि हड्डी के जोड़ों की मूवमेंट कम होने लगती है और इंफ्लामेशन बढ़ने लगती है। जिसकी वजह से सूजन, दर्द, अकड़न जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इस बीमारी में कुछ एंटी-इंफ्लामेटरी फूड्स रामबाण साबित हो सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में दर्द को कम करने वाली शक्ति होती है। इसलिए घर के बड़े-बुजुर्गों को इन चीजों का सेवन जरूर करवाएं।

सेब है गठिया का इलाज

सेब खाकर गठिया के दर्द से राहत पाई जा सकती है। क्योंकि, इसे मोटापे से आई सूजन व इंफ्लामेशन को कम करने में मददगार देखा गया

है। जिससे मोटापे के शिकार लोगों में जोड़ों के दर्द में भी कमी देखी गई।

खाने में अच्छी तरह डालें अदरक और हल्दी

अदरक और हल्दी को आयुर्वेद में कई रोगों की दवा माना जाता है। क्योंकि यह एंटी-इंफ्लामेटरी गुणों का भंडार है। इन्हें औषधि या भोजन के रूप में लेने पर दर्द, सूजन आदि लक्षणों से राहत पाई जा सकती है।

मशरूम है लाभदायक

मशरूम के अंदर फेनोलिक, इंडोलिक, मायकोस्टेरोइड्स, फैटी एसिड, कैरोटेनोइड्स, विटामिन और बायोमेटल जैसे कई सारे एंटी-इंफ्लामेटरी कंपाउंड होते हैं। यह सभी तत्व आर्थराइटिस के इलाज में मदद करते हैं।

स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी

सभी बेरीज में विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है। आर्थराइटिस फाउंडेशन के मुताबिक, इनमें गठिया से लड़ने वाले गुण होते हैं।

अनार खाने के फायदे

अनार के अंदर टैनिन काफी मात्रा में होते हैं। इनमें एंटी-इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। जो घुटनों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसलिए गठिया के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है

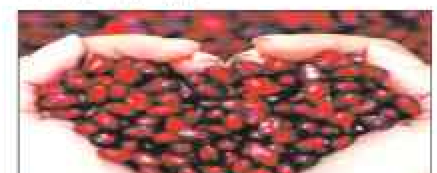

पके कटहल से दूर होंगी कई बीमारियां

गर्मियों के मौसम में कटहल हर कोई खाना पसंद करता है। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। पके कटहल में प्रोटीन भी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जता है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला पोटैशियम हृदय संबंधी समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है। कटहल आपके लिवर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पका कटहल खाने से आपकी सेहत को और कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं.

कटहल के पत्ते भी हैं फायदेमंद

कटहल ही नहीं बल्कि उसके पत्ते भी आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जिनके मुंह में छाले की समस्या होती है उन्हे कटहल के पत्ते को चबाना चाहिए। इससे उनकी मुंह के छालों में काफी आराम मिलेगा।

पाचन मजबूत

गर्मियों में यदि आपको खाना नहीं पच पाता तो आप पके हुए कटहल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यह पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करके आपका वजन सुधारने में भी मदद करता है।

इम्यूनिटी होगी स्ट्रांग

पके कटहल में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन-सी आपके शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट के रुप में कार्य करता है। इसका सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। साथ ही यह आपके शरीर के लिए इम्यूनिटी बुस्टर की तरह काम करता है।

लिवर रहता है स्वस्थ

पके कटहल का सेवन करने से आपका लिवर भी स्वस्थ रहता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व आपके लिवर को मजबूत बनाते हैं। इसमें राइबोफ्लेविन, जिंक, कॉपर और नाइसिन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो लिवर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

दिल रहेगा स्वस्थ

पका हुआ कटहल आपके हृदय के लिए भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसमें पाया जाने वाला पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है।

वजन होगा कम

पके हुए कटहल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं जो आपके शरीर में बढ़ते हुए मोटापे को रोकने में मदद करते हैं। इसका अलावा इसे रेसवेरास्ट्रॉल नाम के एंटीऑक्सीडेंट का भी बहुत ही अच्छा स्त्रोत माना जाता है। यह आपके रक्त के संचार को कंट्रोल करन में भी मदद करता है।

हार्ट के साथ-साथ शरीर के लिए भी फायदेमंद होगी ये एक्सरसाइज

कोई भी बीमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इन दिनों खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी डाइट और व्यायाम करना बहुत ही जरुरी है। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर एकदम फुर्तीला रहता है और आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। आज आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जो आपके हार्ट के साथ-साथ आपके स्वस्थ शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगी। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में.

कार्डियो एक्सरसाइज करें

हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आप कार्डियो एक्सरसाइज को अपनी डेली रुटीन में शामिल कर सकते हैं। इसमें जॉगिंग, साइकिलिंग और वॉक भी शामिल हैं। इससे आपके हृदय की गति तेज होगी और साथ में हृदय की मांसपेशियों की भी एक्सरसाइज होगी।

स्ट्रेचिंग और वेट लिफ्टिंग

आप अच्छे स्वास्थ्य और दिल को स्वस्थ रखने के लिए वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने से आपके शरीर में लचीलापन आता है। साथ ही वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करने से आपका वजन कंट्रोल में रहता है और शरीर में ताकत भी आती है। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज में आप पुशअप्स, स्क्वैट्स, पुलअप्स जैसी एक्सरसाइज को अपनी रुटीन का हिस्सा बना सकते है।

जंपिंग जैक एक्सरसाइज करें

जंपिंग जैक एक्सरसाइज आपके हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे आपका हृदय स्वस्थ रहता है। इससे हृदय की गति भी बहुत अच्छे से होती है।

- सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं।
- इसके बाद ऊपर की ओर उछलें और अपने हाथों को भी ऊपर उठा लें।
- हाथ उठाने के बाद पैरों को भी फैला लें।
- ऐसे ही 10-15 मिनट तक करें और फिर नीचे नार्मल पॉजिशन में आ जाएं।

हर्डल जंप करें

आप हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आप हर्डल जंप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसमें आप किसी हर्डल को लेकर उसके ऊपर से जंप करें। आप डंबल, बॉक्स या फिर किसी स्टेपर का हर्डल के रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों को आप उछल कर पार करें। इस एक्सरसाइज से आपकी हार्ट बीट तेज होगी। हार्ट बीट तेज होने से आपका दिल मजबूत बनेगा।

बर्पी एक्सरसाइज करें

बर्पी एक्सरसाइज आपकी बाजुओं , टांगों और छाती के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इस एक्सरसाइज में स्क्वाट, पुशअप, जंपिंग तीनों चीजे एकसाथ की जाती है। यह तीनों एक्सरसाइज आपको एक सैट में ही करनी पड़ती हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी हृदय गति तेज होगी और दिल की धड़कन एकदम नॉर्मल हो जाएगी।

गर्मी में रखें अपनी आंखों को सुरक्षित

पूरे भारत में गर्मी का हाल बेहाल है। बढ़ती गर्मी के कारण व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहा है। इनमें मुख्य है त्वचा सम्बन्धी रोग और दूसरा है नेत्र सम्बन्धी रोग। दिन-ब-दिन तापमान बढ़ता जा रहा है और भीषण गर्मी असहनीय होती जा रही है। ऐसे में लोग गर्मी से अपना बचाव करते हैं। हम अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक कपड़े और सनस्क्रीन से ढक सकते हैं, लेकिन हमारी आंखों को हम सुरक्षित नहीं कर पाते। गर्मी की वजह से शरीर से ज्यादा तकलीफ हमारी आँखों को होती है। आंखें न केवल हानिकारक यूवी किरणों के सम्पर्क में आती हैं बल्कि गन्दगी, प्रदूषण से भी प्रभावित होती हैं। हम कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनका उपयोग करके वे अपनी आँखों को इस भीषण गर्मी में संक्रमित होने से बचा सकते हैं।

धूप का चश्मा

जिस तरह आप अपने शरीर को कपड़ों से ढकते हैं, दस्ताने से लेकर टोपी तक, उसी तरह आपकी आंखो की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अपने घर से बाहर निकलते समय, यूवी किरणों को सीधे अपनी आंखों में प्रवेश करने से रोकने के लिए आपको सन ग्लास अर्थात धूप का चश्मा अपनी आँखों पर लगाना चाहिए।

कम से कम 8 घंटे सोएँ

गर्मी के दिनों में प्रयास करके अपनी आंखों को पूरा आराम दें। इसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम आठ घंटे की नींद जरूर लें। आठ घंटे की नींद लेने न केवल आपकी आँखें पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं अपितु यह आपके शरीर को भी पूरा आराम प्रदान करता है। साथ ही आपके इम्युनिटी पावर को भी बरकरार रखता है।

ठंडे पानी से बार बार आंखें धोएं

अपनी आंखों को ठंडा रखने के लिए उन्हें ठंडे पानी से बार-बार धोने की कोशिश करें। ठंडा पानी आंखों से गर्मी को दूर करने में मदद करता है और उन्हें बेहतर महसूस कराता है। अपनी आंखों को लुब्रिकेट करें हमारी आंखे नमी खो देती हैं और सूखी और खुजलीदार हो जाती हैं। ऐसे में ढेर सारा पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। जो लोग ऑफिस में लगातार कम्प्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं उन्हें अपनी आँखों को लेकर संजीदगी बरतनी चाहिए। उन्हें कम्प्यूटर पर काम शुरू करने से पहले अपनी आँखों को आई ड्रॉप्स से धोना चाहिए। आठ से दस घंटे लगातार कम्प्यूटर पर काम करने वाले लोगों को ऐसा कम से कम 3 बार करना चाहिए। आँखों में आई ड्रॉप्स डालने से आँखों की चिकनाई बरकरार रहती है।

आंखों पर सनस्क्रीन का प्रयोग करने से बचें

अधिकांश युवा अपने चेहरे को सन स्क्रीन से बचाने के लिए क्रीम का प्रयोग करते हैं। इस क्रीम को लगाते वक्त वे उसको पलकों और भौंह पर भी लगा देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह गलत है। आपको अपनी पलकों या आँखों पर सनस्क्रीन लगाने से बचाव करना चाहिए, क्योंकि इससे वे लाल और खुजलीदार हो सकते हैं।

नुकसानदेह भी है सरसों

भारतीय खानों में अक्सर सरसों के तेल के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरसों का तेल भारतीय मौसम के हिसाब से सेहत और सुंदरता के लिए फायदेमंद माना जाता है। यहां तक कि आयुर्वेद में भी सरसों के तेल का इस्तेमाल कई दवाइयों और उपचार में किया जाता है। सरसो के बारे में हर कोई जानता है। यह भारतीय किचन में मसाले के रूप में उपयोग होने वाली मुख्य सामग्री है। इसका इस्तेमाल अक्सर किसी खास रेसिपी बनाने या तड़का लगाने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं सरसों के तेल का इस्तेमाल भी भारतीय घरों में खूब होता है। बेहतरीन स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए लोग अलग-अलग तरह से इसका उपयोग करते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, चाहे वह सरसों का तेल हो, पेस्ट हो या फिर कच्ची पत्तिया सभी हेल्दी मिनरल्स से भरपूर हैं। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी बेहतरीन स्त्रोत है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा सरसों का सेवन करते हैं, तो इससे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। कई स्थितियों में यह जानलेवा तक साबित हो सकती है। अगर आप भी लंबे समय से सरसों के तेल या बीज का सेवन कर रहे हैं, तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए।

राइनाइटिस का खतरा

सरसों के तेल के लगातार सेवन से कई लोगों को राइनाइटिस हो सकता है। राइनाइटिस में बलगम की झिल्ली में सूजन हो जाती है, जिससे खांसी, छींकना, भरी हुई नाक, नाक से पानी बहाना जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं।

लंग कैंसर के लिए जिम्मेदार

सरसो के तेल में पाया जाने वाला इरुसिक एसिड फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है।

ड्रॉप्सी रोग

ड्रॉप्सी एक खतरनाक रोग है। यह रोग तेल में पूड़ी, कचौड़ी और पकवान बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए सरसों के तेल में अर्जीमोन तेल के मिलावट, सायनाइड के मिलावट के कारण ड्रॉप्सी की संभावना ज्यादा रहती है। इसका उपयोग करने से गुर्दे, हृदय, आदि अंग कमजोर हो जाते हैं। इससे सादा पानी भी पचता नहीं है और शरीर में दूषित पानी जमा होने लगता है, जिससे पेट फूलने की शिकायत होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के हाथ पैर फूल जाते हैं।

एलर्जी की समस्या

अगर आप अपने खाने में अधिक मात्रा में सरसों के दाने या तेल का सेवन करते है, तो एलर्जी हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि सरसों से होने वाली एलर्जी सबसे गंभीर एलर्जी में से एक है। दरअसल, इसके सेवन से हिस्टामाइन में वृद्धि के साथ एनाफिलेक्टिक शॉक भी हो सकता है। पित्ती और त्वचा पर दाने, सांस फूलना, चक्कर आना, उल्टी, गले, चेहरे और आंखों में सूजन इसके मुख्य लक्षण हैं।

दिल के रोग का खतरा

आज भी कई घरो में सरसों के तेल में खाना बनाया जाता है। लेकिन सच मानिए तो हर दिन इसका इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इसमें इरुसिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, जो दिल के लिए खतरा पैदा करता है। सरसों के अधिक उपयोग से मायोकार्डियल पिलिडोसिस की समस्या हो सकती है। जिसमें ट्राइग्लिसराइड के बनने के कारण हृदय की मांसपेशियों के मायोकार्डियल फाइबर में फाइब्रोटिक घाव विकसित होते हैं। जो हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाने के साथ हार्ट फेलियर के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।

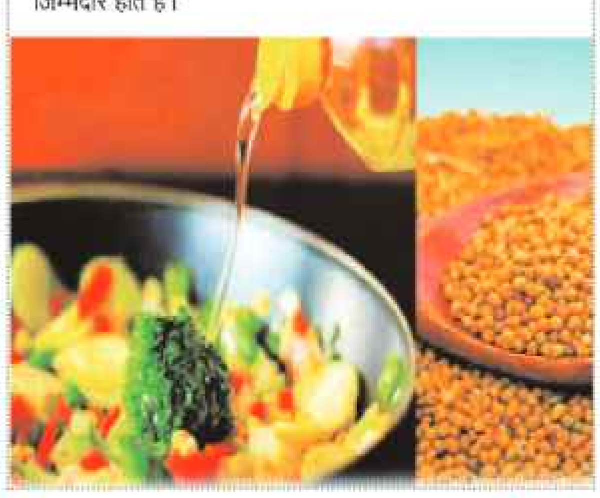

जिले में हुआ भारतमाला घोटाला, एसीबी ने की जांच शुरू, मचा हड़कंप

धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजनांतर्गत रायपुर-विशाखापटनम की प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर के सड़क निर्माण में अभनपुर के बाद अब धमतरी जिले में भी दो ब्लॉकों के अधीन किये गये भ्रष्टाचार का मामला राज्य आर्थिक अपराध अन्वेशण/एंटी करप्शन ब्यूरो के समक्ष पहुंच चुका है जिसे लेकर विभाग ने कलेक्टर धमतरी को पत्र प्रेषित कर संबंधित बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। धमतरी जिले के कुरूद एवं नगरी विकासखंड में किये गये भूअर्जन संबंधी मामलों में लगातार शिकायतों के बाद अब मामला उक्त विभाग के समक्ष पहुंच गया है। खबर के मुताबिक धमतरी जिले से जो फेहरिस्त बनी है उसमें नगरी ब्लॉक का एक मामला जिसमें एक खसरा का 12 बटांकन किया गया है जबकि कुरूद विखं में अनेक लोगों का नाम सामने आ रहा है। धमतरी ब्लॉक इससे अछूता है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध अब शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

भारतमाला 6-लेन एक्सप्रेस वे के नाम पर यह सड़क रायपुर से विशाखापटनम के लिये व्हाया कुरूद, नगरी से होते हुए निकलनी है जिसके लिये इस सड़क निर्माण के क्षेत्र में आने वाले भूमियों को लेकर राजस्व विभाग द्वारा सर्वे कर इन्हें भूअर्जन संबंधी सूची बनाई गई थी। कुरूद के ग्राम सिवनीकला के लोगों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर लंबी-चौड़ी शिकायत करते हुए बताया है कि जो व्यक्ति गांव में कभी देखे नहीं गये, उनके साथ साथ शासकीय विभागों में पदस्थ व्यक्तियों के नाम पर भी एक ही भूमि के खसरा नंबर कई बार बटांकन कर भारी भ्रष्टाचार किया गया है और शासन को लाखों, करोड़ों रूपये का नुकसान पहुंचाया गया है। ग्रामीणों के उक्त कथन के बाद जिला कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच हेतु शिकायतकर्ताओं को तलब भी किया था जिन्होंने महत्वपूर्ण राजस्व दस्तावेज एवं आरआई, पटवारियों द्वारा की गई गंभीर त्रुटियों का प्रमुख प्रमाण प्रस्तुत किया था। कलेक्टोरेट में उपस्थित इन ग्राम के लोगों ने अपने उपरोक्त शिकायतों की पुष्टि करते हुए बयान भी दिया है। यह मामला राज्य आर्थिक अपराध, ईओडब्ल्यू के समक्ष पहुंच जाने से अब ऐसे भूमाफिया और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों में भारी खलबली मची हुई है। संभवतः इनकी गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। अभनपुर विकासखंड में भी कुछ इसी प्रकार का गंभीर मामला उजागर हुआ था जिसमें साधन संपन्न, बाहुबली भूमाफियाओं द्वारा एक ही खसरा नंबर की भूमि को अनेक बटांकन कर लाखों, करोड़ों रूपये की शासन से धोखाधड़ी की गई है। हालांकि इस मामले में सरकार ने सख्ती के साथ कदम उठाते हुए इसे राज्य आर्थिक अपराध अन्वेशण/एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच एजेंसी नियुक्त किया था जिसने अल्पावधि में ही ईओडब्ल्यू ने कुछ लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्यवाही की थी, यह मामला अभी लंबित है। इसी के बाद यह मामला कुरूद और नगरी विखं में भी तूल पकड़ने लगा। कुरूद विखं के लोगों ने अपनी शिकायत में बताया कि भारतमाला एक्सप्रेस वे के लिये अधिग्रहित भूमि में अभनपुर की तर्ज पर कुरूद एवं नगरी विखं में भी ऐसे ही प्रक्रिया राजस्व अधिकारियों ने अपनाई है जिसके चलते साधन संपन्न भूमाफियाओं के साथ साथ आईएफएस, आईएएस के परिवार के लोगों को भी पूर्व में पदस्थ कुरूद, नगरी के अधिकारियों ने एक ही नंबर के भूमि को कई बार बटांकन कर लाखों, करोड़ों रूपये का लाभ पहुंचाया है जिसकी शिकायत अब छग आर्थिक अपराध अन्वेशण ब्यूरो कार्यालय में पहुंच चुकी है और जांच के लिये संबंधित विकासखंड के भूअर्जन संबंधी प्रकरण के समस्त दस्तावेज को अविलंब उपलब्ध कराने कहा गया है। भेजी गई सूची में नगरी विखं अंतर्गत एक खसरा की भूमि 12 बटांकन कर राजस्व विभाग द्वारा गलत तरीके से भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाया गया है जबकि कुरूद में ऐसे अनेक लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। धमतरी ब्लॉक से इस प्रकार की कोई खबर नहीं है।

अविवाहित युवती को जान से मारने की धमकी दे मकान मालिक करता रहा दुष्कर्म

9 माह की गर्भवती को खिलाई गर्भपात की दवा, युवती व नवजात की मौत, आरोपी गिरफ्तार

बालोद। जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्रांतर्गत एक अविवाहित युवती को डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर अवैध संबंध बनाकर गर्भ में पल रहे नवजात शिशु को गर्भपात होने से हुई मृत्यु की घटना करने वाले आरोपी मकान मालिक को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। आरोपी मकान मालिक के द्वारा अविवाहित युवती के साथ कई बार अवैध संबंध बनाकर गर्भवती कर गर्भपात करने के लिए दवाई खिला देने से युवती व नवजात शिशु की जान चली गई। आरोपी के विरुद्ध गंभीर अपराध धारा 90, 91, 105, 238, 351(3), 64(2)एम बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर जिला जेल भेजा गया है। दरअसल 10 मार्च को डौंडीलोहारा थाना के मर्ग क्रमांक 17/2026 धारा 194 बीएनएसएस की मृतिका/पीड़िता का मृत्यु हो गया है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर मृतिका की मां से पुछताछ कर मर्ग इन्टीमेशन लिया। जिसमें बताया कि ये अपनी दो बेटी एवं एक बेटा के साथ लगभग 3 वर्षों से डौंडीलोहारा के सुनील कुमार घरडे के मकान में किराये से रहती है। 9 मार्च के रात करीबन साढ़े 9 से 10 बजे के बीच लड़की मृतिका के कमर, पेट तथा पैर में दर्द होने लगा तब मकान मालिक सुनील कुमार घरडे के द्वारा गोली (दवाई) को मृतिका को दर्द का गोली है, कहकर खिला दिया, जिससे मृतिका छटपटाने लगी व पलंग में चित होकर सो गई। कुछ देर में श्वांस चलना बंद हो गया। जिससे मौके पर मृतिका की मृत्यु हो गई थी।

मृतिका 9 माह की थी गर्भवती

जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण व परिवार के सदस्यों व अन्य गवाहों से पुछताछ कथन से पता चला कि मृतिका जो कि कुंवारी थी तथा यह मकान मालिक सुनील कुमार के द्वारा मृतिका को लगभग एक वर्षों से डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार अवैध शारीरिक संबंध बनाने से वह लगभग 9 माह की गर्भवती थी। आरोपी द्वारा मृतिका व उसके परिवार को अपने किराये के मकान से निकाल देने की धमकी देकर तथा डरा धमका दुष्कर्म को छिपाने का प्रयास किया गया है। आरोपी द्वारा अपराध को छुपाने की नियत से मृतिका को जान बूझकर कोई अज्ञात दवाई को हाथ पैर का दर्द होने का है कहकर खिलाया जिससे मृतिका की मृत्यु हो गया। संपूर्ण मर्ग जांच में डौंडीलोहारा नगर के रामनगर निवासी आरोपी सुनील कुमार घरडे पिता स्व. झुमुक लाल (59) के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी को 11 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह, प्र.आर. विरेन्द्र साहू, प्र.आर. दिगम्बर वर्मा प्र.आर. अरविंद यादव, म.प्र.आर. लिलेश्वरी देवांगन. म.आर. सोनिया, आरक्षक क्रिशेंद्र अजय, पुनम कटरे, डोमेन्द्र भण्डारी, राकेश गावड़े, सायबर सेल टीम बालोद सउनि धरम भुआर्य, प्र.आर. भुनेश्वर सरकाम, विपिन गुप्ता, राहुल कुमार का योगदान रहा।

बालोद में सौंदर्यीकरण कार्य बना मुसीबत, वार्ड क्रमांक 19 के लोग बदबू और मच्छरों से परेशान

पूरे मार्ग पर नाली निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक गंदा पानी, बदबू और मच्छरों की समस्या से क्षेत्रवासियों को लगातार जूझना पड़ेगा

बालोद। शहर में चल रहे सौंदर्यीकरण एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य अब आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। दल्ली चौक से राजनांदगांव रोड तक किए जा रहे सौंदर्यीकरण और सड़क विस्तार कार्य के बाद वार्ड क्रमांक 19 के रहवासी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान पुरानी नालियों को तो तोड़ दिया गया, लेकिन नई नाली का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, जिसके कारण गंदा पानी सड़कों और घरों के आसपास जमा होने लगा है। विशेष रूप से वार्ड-19 के गली नंबर-1, बुढ़ापारा क्षेत्र में नाली की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। नाली व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित होने के कारण गंदा पानी सही तरीके से बह नहीं पा रहा है और कई स्थानों पर पानी जमा होकर सड़ रहा है। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। वार्ड के रहवासियों ने बताया कि नाली नहीं बनने के कारण घरों के सामने गंदा पानी भरा रहता है और कई जगहों पर यह पानी घरों के अंदर तक पहुंचने लगा है। इससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ गया है। शाम होते ही मच्छरों का ऐसा बवंडर बन जाता है कि लोगों का घरों के बाहर बैठना या बच्चों का खेलना तक मुश्किल हो गया है। इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। इस समस्या से स्थानीय व्यापारी भी अछूते नहीं हैं। राजनांदगांव रोड के किनारे स्थित कई दुकानों तक गंदे पानी की बदबू पहुंच रही है, जिससे ग्राहकों का आना-जाना कम हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि यदि जल्द ही नाली निर्माण नहीं कराया गया तो इसका सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ेगा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर को सुंदर बनाने के नाम पर किया जा रहा यह कार्य आम जनता की परेशानियों को बढ़ा रहा है। यदि समय रहते नाली निर्माण और पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

शीघ्र ही नाली निर्माण कार्य पूर्ण कराने का दिया गया था आश्वासन

स्थानीय नागरिक उमेश कुमार सेन ने इस गंभीर समस्या की ओर प्रशासन और संबंधित विभागों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि वार्ड क्रमांक 19, गली नंबर 1 बुढ़ापारा क्षेत्र की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनती जा रही है। यदि शीघ्र ही नाली निर्माण और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्र के रहवासियों को और अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि जय स्तंभ चौक से मधु चौक के आगे तक सड़क के किनारे नाली निर्माण का कार्य अधूरा होने के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है। स्थानीय व्यापारियों एवं नागरिकों की लगभग एक माह पूर्व लोक निर्माण विभाग (बाइक्ष) के अधिकारियों से मौखिक मुलाकात भी हुई थी, जिसमें अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही नाली निर्माण कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि समय बीतने के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ती जा रही है। नागरिकों का मानना है कि जब तक इस पूरे मार्ग पर नाली निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक गंदा पानी, बदबू और मच्छरों की समस्या से क्षेत्रवासियों को लगातार जूझना पड़ेगा।

बेमेतरा में होटल व प्रतिष्ठानों की जांच 10 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए उपयोग में

बेमेतरा। जिला बेमेतरा में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। आज 12 मार्च 2026 को खाद्य विभाग की टीम ने शहर में संचालित विभिन्न होटल, ढाबा और खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कुल 10 घरेलू गैस सिलेंडर विभिन्न प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक कार्यों में उपयोग करते हुए पाए गए। इनमें गुजराती स्वीट्स से 2 सिलेंडर, चाचा भतीजा से 1 सिलेंडर, जय मां शीतला ढाबा से 1 सिलेंडर, मनोहर चाय से 2 सिलेंडर, आरसी किचन से 2 सिलेंडर, यादव पुड़ी सब्जी से 1 सिलेंडर तथा अनिल स्वीट्स से 1 सिलेंडर बरामद किए गए। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही किया जाना निर्धारित है, जबकि होटल, ढाबा या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इसका उपयोग करना नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2007 के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी होटल संचालकों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में न करें और नियमानुसार केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले में इस प्रकार की जांच आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत बेमेतरा में अरहर खरीदी कार्य का शुभारंभ

बेमेतरा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा योजना) के अंतर्गत जिले के परपोड़ी उपार्जन केन्द्र में अरहर खरीदी कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। कृषि विभाग, नेफेड, मार्कफेड तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में एक कृषक से 15 क्विंटल अरहर की खरीदी कर खरीदी कार्य की औपचारिक शुरुआत की गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा अरहर (तुअर) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिस पर पंजीकृत किसानों से उपज की खरीदी की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना, दलहन-तिलहन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में कुल 9 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ चना, अरहर, सरसों सहित विभिन्न दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। उपार्जन केन्द्रों में तौल व्यवस्था, बारदाना, पेयजल, छाया तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अधिकारियों ने बताया कि खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा रही है। किसानों की उपज की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे के माध्यम से की जा रही है तथा खरीदी के बाद भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा समुचित निगरानी भी की जा रही है। कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे अपने निकटतम उपार्जन केन्द्र में निर्धारित समयानुसार अपनी उपज लेकर आएं और शासन द्वारा संचालित इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं।

साथ ही किसानों को यह भी बताया गया कि खरीदी केन्द्रों में आवश्यक दस्तावेज एवं पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ही उपज लाना सुनिश्चित करें, जिससे खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जिला प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा खरीदी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शासन की इस पहल से जिले के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और दलहन-तिलहन फसलों के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन

बेमेतरा। शासकीय हाई स्कूल नरी में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन खण्डसरा की टीम उपस्थित हुई। टीम का नेतृत्व कर रहे डॉ. रिषभ शर्मा ने संस्था के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने तंबाकू उत्पाद से होने वाली हानि के विषय मे बताया साथ ही तंबाकू उपयोग से जुड़े कारक, धूम्रपान के विविध प्रकार, तंबाकू और व्यक्तिगत स्वरूप, धूम्रपान छोड़ने के नुस्खे, तंबाकू छोड़ने के फायदे,कोटपा की विभिन्न धाराओं, एवं तंबाकू के विभिन्न दुष्परिणामों से अवगत कराया। संस्था के प्राचार्य सुनील कुमार झा ने दल के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो जानकारी बच्चों को प्रदान की गई वह बच्चों के साथ उनके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से यह कार्यक्रम तंबाकू नियन्त्रण एवं नशा उन्मूलन की दिशा मे एक अच्छा कदम है। कार्यशाला में विद्यार्थियों के लिए तंबाकू दुष्प्रभाव एवं नियंत्रण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें संस्था के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने विषय पर अपनी कल्पनाओं को चित्र के माध्यम से कागज पर उकेरा। इस प्रतियोगिता में कु. डिम्पल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुमन एवं प्रिया क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहीं। विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। साथ ही समस्त प्रतिभागियों को सांत्वना स्वरूप प्रशस्ति पत्र दिए गए।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की उपस्थिति में दुर्ग में राष्ट्रीय लोक अदालत आज

पोर्टफोलियो जज माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी भी करेंगे शिरकत — जिला न्यायालय दुर्ग में उत्साह का वातावरण

दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 मार्च 2026 को जिला न्यायालय दुर्ग एवं उसके अधीनस्थ न्यायालयों में किया जा रहा है।

उनके करकमलों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभ आगाज़ किया जाएगा, जो त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण न्याय की भावना को और सुदृढ़ करेगा।

इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री रमेश सिन्हा राष्ट्रीय लोक अदालत का सुभारंभ करेंगे। माननीय के करकमलों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभ आगाज़ त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण न्याय की भावना को और सुदृढ़ करेगा। उनकी उपस्थिति से यह प्रयास न केवल त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करेगा, बल्कि न्याय व्यवस्था में विश्वास और समर्पण की भावना को भी प्रोत्साहित करेगा। कार्यक्रम की शोभा माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं पोर्टफोलियो जज, जिला दुर्ग की उपस्थिति से और अधिक बढ़ेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा लोक अदालत की व्यवस्था को आमजन के लिए अधिक सुलभ, प्रभावी एवं त्वरित न्याय प्रदान करने वाला मंच बनाने के उद्देश्य से निरंतर विशेष बल दिया गया है। उनके मार्गदर्शन में यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायिक अधिकारी प्री-लिटिगेशन तथा लंबित प्रकरणों दोनों में पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित करें, जिससे विवादों का त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण संभव हो सके।

माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वयं दिनांक 26.02.2026 एवं 11.03.2026को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई, तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। उनके मार्गदर्शन में जिला न्यायालय दुर्ग द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए तैयारियाँ की गई हैं, ताकि माननीय मुख्य न्यायाधीश की दूरदर्शी सोच को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके।

माननीय महोदय के आगमन से पूरे जिले में विशेष उत्साह एवं सक्रियता का वातावरण है। न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, विभिन्न बैंकों तथा शासकीय विभागों के सहयोग से लोक अदालत को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय दुर्ग सहित परिवार न्यायालय दुर्ग, सिविल न्यायालय भिलाई-3, पाटन, धमधा एवं अन्य न्यायालयों में कुल 39 पीठों का गठन किया गया है, जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण निराकरण का प्रयास किया जाएगा।

लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, दीवानी वाद, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण तथा बैंक, विद्युत एवं दूरसंचार से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को रखा जाएगा। न्यायिक अधिकारी पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का समाधान करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे समय और संसाधनों की बचत के साथ सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ावा मिलेगा।

लोक अदालत के प्रति अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक लोक अदालत के लाभों की जानकारी पहुँचाने के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिसके द्वारा लोक अदालत की प्रक्रिया तथा उसके लाभों के बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है।लोक अदालत के दिन मोबाइल वैन की विशेष व्यवस्था उन पक्षकारों के लिए उपलब्ध रहेगी, जो वृद्धावस्था, बीमारी अथवा अन्य कारणों से न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में मोबाइल वैन संबंधित पक्षकारों तक पहुँचकर उन्हें लोक अदालत की प्रक्रिया से जोड़ने में सहयोग करेगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत के माध्यम से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण न्याय का लाभ प्राप्त हो सके।

इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए प्रकरणों की पहचान, पक्षकारों से संपर्क तथा प्री-लिटिगेशन मामलों के समाधान की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया गया है। लोक अदालत की कार्यवाही भौतिक एवं वर्चुअल दोनों माध्यमों से आयोजित की जाएगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के पक्षकार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिना लंबी यात्रा किए अपने मामलों का निराकरण करा सकेंगे। कार्यक्रम के अवसर पर न्यायालय परिसर में केन्द्रीय जेल दुर्ग के बंदियों द्वारा तैयार हस्तशिल्प, चित्रकला एवं अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-विक्रय स्टॉल भी लगाया जाएगा, जिससे उनके कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा और पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक पहल को बल मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा।

जिला न्यायालय दुर्ग में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विशेष उत्साह एवं सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण व्याप्त है, और सभी संबंधित संस्थाएँ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। माननीय महोदय के आगमन से कार्यक्रम की गरिमा में अभिवृद्धि होगी । यह आयोजन न केवल विवादों के त्वरित समाधान का माध्यम बनेगा, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति आमजन के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। Email : loktantraprahrinews@gmail.com